"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008—श्रावण 17, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री विवेक ढॉड, भा. प्र. से. (1981) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री ढॉड द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. (1986) केवल सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—श्रीमती संगीता पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 21-07-2008 से 02-08-2008 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2008 तथा 03-08-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता पी., आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती संगीता पी., को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संगीता पी., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती संगीता पी., के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. डी. झा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, [illegible]पुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/3/2003/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर को दिनांक 30-06-2008 से 03-07-2008 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला, आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. शुक्ला के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी., पिल्ले, भा. प्र. से., आयुक्त, रोजगार गारण्टी योजना, रायपुर को दिनांक 18-08-2008 से 25-08-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 एवं 17 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले, आयुक्त, रोजगार गारण्टी योजना, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/14/2007/1/2.—श्री रजत कुमार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा को दिनांक 16-06-2008 से 20-06-2008 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रजत कुमार, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रजत कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/16/2007/1/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 27-06-2008 से 05-07-2008 तक (9 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 6-7-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 21-07-2008 से 26-07-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 27 जुलाई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल आगामी आदेश तक विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 825/662/2008/1-8/स्था.—श्री टामन सिंह सोनवानी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 25-7-2008 से 5-8-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दुबई (यू. ए. ई.) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टामन सिंह सोनवानी को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टामन सिंह सोनवानी, अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक 1476/429/2008/1-8/स्था.—श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 7-5-2008 से 16-5-2008 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद गुप्ता को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 9-13/2008/1-8.—श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला (रा. प्र. से.) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं पदेन उप-सचिव, परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, गृह एवं परिवहन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक 827/665/2008/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिनांक 29-4-2008 से 3-5-2008 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त अवकाश उपरान्त श्री ए. के. टोप्पो को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक 829/668/2008/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 562-63/344/2008/1-8/स्था., दिनांक 29-5-2008 द्वारा श्री अनुराग लाल, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1-7-2008 से 5-7-2008 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 29-5-2008 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक 7108/1902/21-ब/छ. ग./2008.--राज्य शासन, द्वारा केन्द्र सरकार से इस राज्य को प्राप्त नोटरियों के 200 पदों के परिप्रेक्ष्य में, जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुए प्रत्येक जिलों, तहसीलों, उप तहसीलों एवं विकासखण्डों में नोटरियों के पदों की संख्या पुनर्निर्धारित किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2906/947/21-ब/छ. ग./08 दिनांक 04-04-2008 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 05 के कालम 03 में जिला राजनांदगांव के तहसील चौकी में नोटरी के पूर्व स्वीकृत पदों की संख्या 03 के स्थान पर 01 तथा कालम 05 में 04 के स्थान पर 02 पद तथा नोटरी के कुल पदों की संख्या 40 के स्थान पर 38 पढ़ा जावें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2008

क्रमांक 6856/डी-2190/21-ब/छ. ग./2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री लखन लाल तिवारी, अधिवक्ता, पेण्ड्रारोड को फास्ट ट्रेक कोर्ट पेण्ड्रारोड में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2008

क्रमांक 6857/2190/21-ब/छ. ग./2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पवन कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर को नियमित न्यायालय पेण्ड्रारोड में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक 7126/2185/21-ब/छ. ग./2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कृष्ण लाल गबेल, अधिवक्ता, सक्ती को दिनांक 03-09-2008 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिये निष्ठापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा के साथ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक 1504/2382/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नया रायपुर, विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है. उक्त विकास योजना अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है.

नया रायपुर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. कलेक्टर, जिला रायपुर (छ. ग.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर (छ. ग.)
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ. ग.)

नया रायपुर विकास योजना 2031, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

No. 1504/2382/32/07.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Naya Raipur Development Plan, 2031 submitted by Naya Raipur Development Authority, Raipur under sub section (3) of Section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for general information as required by sub section (4) of Section 19 of the said Adhiniyam.

The copy of the approved Development Plan 2031 shall be available during office hours for inspection in the following office :

1. Collector, District Raipur (C. G.)
2. Chief Executive Office, Naya Raipur Development Authority, Raipur (C. G.)
3. Joint Director, Divisional office, Town & Country Planning, Raipur (C. G.)

The Naya Raipur, Development Plan 2031 shall come in to operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub section (5) of Section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक 293/13/ऊ. वि./2008.—राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम सं. 54) की धारा 5 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 30-06-2008 की अवधि से आगामी 31-07-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 11-2/2008/16.—व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यू. के. मेश्राम, सहायक श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कार्मिक संघों का जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का "एडीशनल रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन" नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2008

क्रमांक एफ 1-7/2004/25/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति उपरांत पद संरचना के अंतर्गत 15 जिलों हेतु कार्यक्रम निरीक्षक वेतनमान 5000-8000 के स्वीकृत 15 पदों को समर्पित करते हुए, क्षेत्र संयोजकों के कुल 12 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पद संख्या	अतिरिक्त स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
1.	क्षेत्र संयोजक	5500-8000	18	12	01 पद प्रति जिला (रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा को छोड़ कर)

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 277/20454/वित्त विभाग/ब-3/2008 दिनांक 12-6-2008 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 4-12/04/11/6.—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (संशोधित नियम 1998) अनुकूल 2000 (क्र. उप सन् 1998) अनुसूची 1 की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त इम्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची में दर्शित दर के अधिकतम शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि करता है.

अत: उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात् :—

अनुसूची-1

अधिकतम शुल्क
[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

क्र.	**दस्तावेज या कार्य जिसके संबंध में शुल्क देय है**	**अधिकतम शुल्क**
1.	धारा 58 के अधीन कथन	551 रुपये
2.	धारा 60 के अधीन कथन	110 रुपये
3.	धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	110 रुपये
4.	धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	56 रुपये
5.	धारा 63 के अधीन सूचना	110 रुपये
6.	धारा 64 के अधीन आवेदन	56 रुपये
7.	धारा 66 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन फर्मों के रजिस्ट्रर एवं दस्तावेजों का निरीक्षण.	27
8.	धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां प्रत्येक 100 शब्द या उसके भाग के लिए.	12

परंतु राज्य सरकार प्रत्येक दो वर्ष में उपरोक्त दर के अधिकतम पांच प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए दर में वृद्धि कर सकेगी.

टिप्पणी :— ऐसे मामले में जहां आवेदक धारा 67 के अधीन फर्मों के रजिस्टर में प्रतियों की शीघ्र अर्थात् पांच कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षा करता है, वहां फीस की दुगुनी रकम के साथ पृथक आवेदन फाईल करेगा और सक्षम प्राधिकारी, पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रतियां देगा.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 4-5/08/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 की धारा 7 एवं नियम 4 के शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची

नियम 4 देखिये

फीस

1.	धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण	-	रुपये 1500/-
2.	धारा 7 के अधीन महिला स्व सहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण	-	रुपये 250/-
3.	धारा 7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	-	रुपये 300/-
4.	धारा 7 के अधीन युवा मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	-	रुपये 150/-
5.	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	-	रुपये 200/-
6.	धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन (क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन - (एक) क्रय तथा विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु	-	क्रय का 2 प्रतिशत और विक्रय का 5 प्रतिशत.
	(दो) प्रत्येक दान के लिए	-	रुपये 5000/-
	(ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर समपति के अन्यथा उपयोग हेतु.	-	रेखांक (प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रुपये 10000/- इसमें से जो भी अधिक हो.
7.	धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष	-	रुपये 200.00
8.	धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्ष	-	रुपये 200.00
9.	धारा 29 के अधीन प्रतियां	-	रुपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य
		-	रुपये 40.00 प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक
		-	रुपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर.
		-	रुपये 100.00 निरीक्षण विवरणी/ मूल फाईल.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

विषय :- कृषि उपज मंडी समिति सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा में निर्वाचित कृषक सदस्य क्षेत्र क्रमांक 53/4 नन्दौर खुर्द के आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम.

सन्दर्भ :- विभाग का प्रत्र क्रमांक/3149/डी-15/239/2005/14-2 रायपुर दिनांक 23-5-2008.

क्रमांक/4136/डी-15/239/2005/14-2.—विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अंतर्गत (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 26 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, कृषि उपज मण्डी समिति सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के क्षेत्र क्रमांक 53/4 नन्दौर खुर्द के कृषक सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

क्र.	कार्य का स्वरूप	वह तारीख तक/ को पूरा किया जाना है	दिन	किसके द्वारा	संदर्भ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिये समय अनुसूची जारी करना.	23-07-2008	बुधवार	राज्य शासन	नियम 26
2.	निर्वाचन की सूचना	30-07-2008	बुधवार	जिला निर्वाचन अधिकारी	नियम 27
3.	मतदाता केन्द्र की स्थापना तथा उसका प्रचार-प्रचार.	04-08-2008	सोमवार	जिला निर्वाचन अधिकारी	नियम 21
4.	नाम निर्देशन प्राप्त किये जाने का सातवां/ अंतिम दिन.	11-08-2008	सोमवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 29 एवं 30
5.	नामांकन पत्र की जांच	13-08-2008	बुधवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 32
6.	नाम निर्देशन की वापसी	18-08-2008	सोमवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 34
7.	मतदान	30-08-2008	शनिवार	कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग आफिसर	
8.	मतगणना परिणाम की घोषणा	02-09-2008	मंगलवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 74 एवं 78

(अ) मतदान का समय 7.00 पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय नियत किया जाता है. जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

विषय :- कृषि उपज मंडी समिति कुरूद, जिला धमतरी के निर्वाचित कृषक सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18/2 ग्राम जी-जामगांव के आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम.

सन्दर्भ :- विभाग का प्रत्र क्रमांक/3075/डी-15/239/2005/14-2 रायपुर दिनांक 20-5-2008.

क्रमांक/4137/डी-15/239/2005/14-2.—विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अंतर्गत (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 26 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, कृषि उपज मण्डी-समिति कुरूद, जिला धमतरी के क्षेत्र क्रमांक 18/2 जी-जामगांव के निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

क्र.	कार्य का स्वरूप	वह तारीख तक/ को पूरा किया जाना है	दिन	किसके द्वारा	संदर्भ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिये समय अनुसूची जारी करना.	23-07-2008	बुधवार	राज्य शासन	नियम 26
2.	निर्वाचन की सूचना	30-07-2008	बुधवार	ज़िला निर्वाचन अधिकारी	नियम 27
3.	मतदाता केन्द्र की स्थापना तथा उसका प्रचार-प्रचार.	04-08-2008	सोमवार	जिला निर्वाचन अधिकारी	नियम 21
4.	नाम निर्देशन प्राप्त किये जाने का सातवां/ अंतिम दिन.	11-08-2008	सोमवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 29 एवं 30
5.	नामांकन पत्र की जांच	13-08-2008	बुधवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 32
6.	नाम निर्देशन की वापसी	18-08-2008	सोमवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 34
7.	मतदान	30-08-2008	शनिवार	कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी	
8.	मतगणना परिणाम की घोषणा	02-09-2008	मंगलवार	रिटर्निंग आफिसर	नियम 74 एवं 78

(अ) मतदान का समय 7.00 पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय नियत किया जाता है. जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक-1632/एसटीए/टीसी/08.—

छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य के मध्य सम्पन्न प्रस्तावित पारस्परिक यातायात समझौता में संशोधन संबंधी अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अधिसूचना क्र.-एफ 5-58/दो/आठ-परि./04, रायपुर दिनांक 25 अगस्त 05

क्रमांक-एफ 5-58/दो/आठ-परि./08.—रायपुर दिनांक 15-07-2008 जैसा कि राज्य शासन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य की सरकार के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 (सं. 59 सन् 1988) की धारा 88 की आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पारस्परिक यातायात समझौता किया गया है।

अतएव मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (5) के अनुसरण में पूर्व में जारी किये गये जारी प्रस्तावित पारस्परिक यातायात समझौता की अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 5-58/दो/आठ-परि./04, रायपुर दिनांक-25 अगस्त 05 प्रकाशित किया गया है, उसे अतिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार एवं उड़ीसा सरकार के मध्य पारस्परिक यातायात समझौता से ऐसे व्यक्तियों की जिनके इस संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी हेतु निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया जाता है।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि समझौता का संशोधित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के "राजपत्र" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिवस पश्चात् प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा विचार किया जावेगा, यदि कोई आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करना चाहते है, तो प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, डी0के0एस0 भवन, रायपुर को संबोधित करते हुए संशोधन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् 30 (तीस) दिवस के भीतर सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

समझौते का संशोधित प्रस्ताव

यह कि छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य के मध्य अंतर्राज्यीय मार्गो पर वाहनो के संचालन को नियंत्रित एवं नियमन करने हेतु निर्णय दिया गया है। अतएव निबंधनों एवं शर्तो के अधीन पारस्परिक यातायात समझौते में निम्नानुसार संशोधन प्रकाशित किया जाता है:-

1. <u>प्रकृम वाहन के परमिटः-</u>

(क) प्रक्रम वाहनों के लिए अर्न्तराज्यीय मार्ग का आशय है ऐसे मार्ग जैसा कि सहमति हुई हो तथा फेरो की संख्या एवं परमिट की संख्या परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होगी।

(ख) संबंधित राज्य के प्रकृम वाहन पारस्परिक करारकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार उस राज्य में पड़ने वाले मार्ग के भाग के लिए कर का भुगतान करेंगे।

(ग) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के संचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया एवं भाड़ा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, एक राज्य द्वारा जारी किये गये टिकिट पारस्परिक राज्य में वैध माने जायेंगे।

(घ) परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित मार्गो पर जब तक पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्थायी परमिट स्वीकृत नही किये जाते, संबंधित राज्य के नॉमिनी को परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएगें।

सहमत मार्गो के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट पर कर उसी भॉति देय होगा जैसा कि सहमत मार्गो के लिए स्थायी परमिट पर देय होता है।

(ड.) पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 88(7) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट स्वीकृत करने हेतु सामान्य सहमति जैसी और जब आवश्यक हो दे सकेंगे।

(च) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए, यदि प्रकृम वाहन मूल पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अर्न्तराज्यीय मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) यदि परिशिष्ट 'अ' में उद्धित मार्गो की दूरी के संबंध में कोई मतभेद पाया जाता है तो वह दोनों राज्यों के बीच पत्र व्यवहार के माध्यम से सुधार लिया जाएगा और यह करार के उपान्तंरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ज) इस करार के प्रभावशील के समय जो परमिट अस्तित्व में है उन्हें परिशिष्ट 'अ' में सहमत मार्गो के विरूद्ध जारी किया गया माना जाएगा।

(झ) यदि मार्ग की दूरी 250 कि.मी. से अधिक है तो संचालित सेवाएं एक्सप्रेस सेवा के रूप में मानी जावेगी।

(ञ) ऐसे मामलों में प्रक्रम यात्री सेवा प्रतिदिन दो एकल फेरा परमिट स्वीकृत हो और गृह राज्य से संचालन प्रारम्भ होता हो तो उस यात्री वाहन को गृह राज्य में ही रात्री विश्राम करना होगा।

(ट) सभी अंतर्राज्जीय मार्गो पर गृह राज्यों के प्रक्रम वाहनों को पारस्परिक राज्यों के प्रक्रम वाहनों पर समय चक्र में प्राथमिकता प्राप्त रहेगी।

2 <u>स्थायी परमिट के अर्न्तगत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन</u> :-

मोटर केब के लिए संविदा वाहन परमिंट पर एक दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। प्रतिहस्ताक्षर से आच्छादित मोटरकेब पारस्परिक राज्य के वाहन कर का भुगतान प्रतिहस्तरित राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार करेंगे।

3 <u>अस्थायी परमिट के अन्तर्गत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन</u> :-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत संख्या पर प्रतिबंध के बिना मोटरकेब के लिये, प्रत्येक माह अस्थायी परमिट एक वापसी फेरा हेतु, विशिष्ट अर्न्तराज्यीय मार्ग के दो सिमांन्तो को जोड़ने के लिए, बिना प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के जारी किये जायेगें, पारस्परिक राज्य का वाहन कर अस्थायी परमिट की वैध समयावधि के लिए पारस्परिक राज्य को देय होगा।

4 <u>स्थायी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः</u>–

निजी सेवा यानों को स्वीकृत स्थायी अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्तरित राज्य वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा तथा ऐसे वाहनों का मोटरयान कर प्रतिहस्तरिक्षत राज्य कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किया जावेगा।

5 <u>अस्थाई अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः</u>-

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत निजी सेवा यानों को अधिकतम 30 दिवस के लिए परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत किया जावेगा। चाहे निर्धारित अंतर्राज्जीय मार्ग के लिए हो या किसी स्थान के लिए और ऐसे अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किए बिना स्वीकृत किए जा सकेगें, परन्तु करारकर्त्ता राज्य का मोटरयान कर उस राज्य के कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान करना होगा।

6 <u>स्थायी परमिट के अन्तर्गत मालयान का सचालन</u> :-

(क) प्रत्येक राज्य के मालयान परमिट पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत परमिट की संख्या पर प्रतिवंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

(ख) वाहन अपनी वापसी यात्रा में अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्ही दो बिन्दुओं के बीच उस राज्य के किसी स्थान व मार्ग पर माल को चढ़ाने व उतारने का कार्य नहीं करेगा।

परन्तु अग्रेषित यात्रा में पारस्परिक राज्य के किसी बिन्दु पर माल उतारने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु उस राज्य में कोई माल चढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे माल वाहनों का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत के अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात परमिट जारी करने के विवरण सहित संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जावेगा।

(ग) पारस्पिरिक एक दूसरे राज्य की माल वाहनें प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के अन्तर्गत संचालित होती है तो प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के लिए रूपयें 6000/-प्रतिवर्ष वाहन कर देय होगा। कर

का भुगतान न्यूनतम एक वर्ष के लिए अग्रिम में किया जावेगा, बशर्ते परमिट वैध हो एवं दोनों राज्य सहमति के आधार पर कर की दर में परिवर्तन कर सकते है तथा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में संग्रहित करने एवं उक्त बैंक ड्राफ्ट को परमिट जारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य के प्राधिकार को भेजा जायेगा।

(घ) यदि प्रतिहस्ताक्षर परमिटधारी कर का भुगतान पूर्व में भुगतान किये गये कर की वैधता समाप्त होने की तिथि से 2 माह के अन्दर करने में असफल रहता है, तो प्रतिहस्ताक्षर निरस्त माना जाएगा और यदि वाहन स्वामी नवीनीकरण के लिए उपस्थित होता है तो रू. 1000/- जुर्माने की राशि भुगतान करने पर उसे अनुमति दी जाएगी।

(ड.) जो मालयान अपने मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है, उसके परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

7 <u>अस्थायी परमिट के अर्न्तगत मालयान का संचालनः-</u>

प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी पारस्परिक राज्य की पूर्व सहमति के बिना मालयानों के लिए किसी भी संख्या में अस्थायी परमिट जारी कर सकेंगे। इस प्रकार जारी किया गया अस्थायी परमिट निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगाः-

(क) मालयान का उपयोग अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्ही दो बिन्दुओं पर माल को चढ़ाने व उतारने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) ऐसे माल वाहन का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति के समय अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने पश्चात् परमिट जारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जायेगा।

8 <u>सामान्यः-</u>

(क) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अन्तर्गत पारस्परिक राज्य के कोरीडोर श्रेणी के मार्ग के लिए पारस्परिक राज्य का कर परमिट अनुसार निर्धारित दूरी के लिए गृह राज्य द्वारा लिया जाएगा एवं उक्त दूरी के कोरीडोर मार्ग के संबंध में पारस्परिक राज्य द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा।

(ख) पारस्परिक राज्य कर भुगतान प्राधिकार पत्र एवं इस करार के अनुसार अर्न्तराज्यीय मार्गो पर संचालित मोटरयान के परिचालक लायसेंस को मान्यता प्रदान करेगें।

(ग) पारस्परिक राज्य के वाहन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के हो, और जिनका उपयोग अनार्थिक उद्देश्य से किया जाता हो मोटरयान कर के भुगतान से पूर्णतः मुक्त होगें।

(घ) नवीन सड़क निर्माण की स्थिति में प्रकृम वाहन को समझौते में उल्लेखित अन्र्तराज्यीय मार्ग के विचलित मार्ग से संचालन की अनुमति संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार के अनुमोदान पश्चात् ही दी जाएगी।

(ङ.) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत अंतर्राज्जीय मार्गो पर संचालित यात्री वाहनों में उल्लेखित प्रभेदक बोर्ड वाहन के सामने की ओर प्रदर्शित करेंगे जिस पर उड़िया एवं हिन्दी भाषा में मार्ग का स्थान एवं गंतब्य-स्थल का उल्लेख होगा। प्रक्रम वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(च) पारस्परिक राज्य एक दूसरे राज्य की प्रकृम वाहन को अपने अधिसूचित बस स्टेण्ड़ में यात्री चढ़ाने एवं उतारने की अनुमति प्रदान करेगें।

(छ) यह पारस्परिक करार तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक दोनों राज्यों के मध्य इसका पुर्नविलोकन न हो और एक नवीन करार प्रभावशील न हो जाए अथवा आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की सूचना देकर करार को विखण्ड़ित नहीं कर दिया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट– " अ "

उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित संचालन हेतु अन्तर्प्रान्तीय मार्गों का विवरण–

स.क्र.	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में		कुल योग	परमिट संख्या		फेरो की संख्या		कुल कि.मी. संचालित		सेवा का प्रकार
		उड़ीसा	छत्तीसगढ़		उड़ीसा	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ द्वारा उड़ीसा में	उड़ीसा द्वारा छत्तीसगढ़ में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आउल से भिलाई व्हाया चण्डीखोल, कटक, संबलपुर सुहेला	472	209	681	2	2	2	2	944	418	एक्सप्रेस
2	बरगढ़ से बिलासपुर व्हाया सारंगढ़, भटगांव, शिवरीनारायण	120	159	279	2	2	2	2	240	318	एक्सप्रेस
3	बरगढ़ से कोरबा व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, चांपा	120	175	295	1	2	1	2	240	175	एक्सप्रेस
4	बरगढ़ से रायगढ़ व्हाया भटली, नवपड़ा, चन्द्रपुर	92	87	179	4	4	8	8	736	696	साधारण
5	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सोहेला, सरिया	46	181	227	2	2	4	4	184	724	साधारण
6	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सारंगढ़, रूचदा, सरिया	52	87	139	2	2	4	4	208	348	साधारण
7	बरगढ़ से शक्ति व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, खरियार	76	120	196	2	2	4	4	304	480	साधारण
8	बारीपड़ा से रायपुर व्हाया केंवझर, सम्बलपुर, लोहरछटी	355	181	536	2	2	2	2	710	362	एक्सप्रेस
9	बरपाली से रायपुर व्हाया बरगढ़ लोहरछटी, बसना, आरंग	128	181	309	2	2	2	2	256	362	एक्सप्रेस
10	बेलपहाड़ से अम्बिकापुर व्हाया रायगढ़	45	214	259	2	2	2	2	90	428	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	बरहमपुर से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, जगदलपुर	404	150	554	2	2	2	2	808	300	एक्सप्रेस
12	बरहमपुर से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द, आरंग	473	109	582	4	2	4	2	946	436	एक्सप्रेस
13	भवानीपटना से जगदलपुर व्हाया जुनागढ़, नवरंगपुर, कोटपाड, चांदली	384	22	406	2	2	2	2	768	44	एक्सप्रेस
14	भवानीपटना से रायपुर व्हाया धरमगढ़, देवभोग	80	229	309	2	2	2	2	160	458	एक्सप्रेस
15	भीखमपाली से शाना (आस्था) व्हाया कनकतोरा, रायगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी	36	199	235	2	2	4	4	144	796	साधारण
16	भुनेश्वर से भिलाई व्हाया कटक, धनकेनाल, संबलपुर, लोहरछटी	422	209	631	2	2	2	2	844	418	एक्सप्रेस
17	भदरक से रायपुर व्हाया केंवझर, लोहरछटी	400	181	581	2	0	2	0	0	362	एक्सप्रेस
18	भुनेश्वर से दुर्ग व्हाया कटक, धनकनाल, संबलपुर, बरगढ़, लोहरछटी, रायपुर, भिलाई	422	235	657	2	0	2	0	0	470	एक्सप्रेस
19	बिलासपुर से बरहमपुर व्हाया, रायपुर, महासमुन्द, भवानीपटना	338	227	565	2	2	2	2	676	454	एक्सप्रेस
20	बलांगीर से रायपुर व्हाया बरगढ़, सोहेला, सरायपाली	195	181	376	2	2	2	2	390	362	एक्सप्रेस
21	भवानीपटना से रायपुर व्हाया खरियार	130	109	239	2	2	2	2	260	218	साधारण
22	भवानीपटना से दुर्ग व्हाया खरियार, रायपुर	130	149	279	2	2	2	2	260	298	एक्सप्रेस
23	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया बोरीगुमा	121	60	181	2	1	4	2	242	240	साधारण
24	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया चांदली	121	21	142	2	2	4	4	484	84	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया कोरापुर, ज्योपुर, बोरीगुमा, धनपुजी, जगदलपुर, कांकेर	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	एक्सप्रेस
26	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया सोनबेड़ा, कोरपुट, ज्योपुर, उमरकोट	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	एक्सप्रेस
27	धरमगढ़ से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड़, महासमुन्द, आरंग	205	109	314	4	4	4	4	820	436	एक्सप्रेस
28	हाथीबांधा से रायपुर व्हाया खरियाररोड़	115	109	224	2	2	4	4	460	436	साधारण
29	जगदलपुर से धमतरी व्हाया करपावंट, सिनसारी, उमरकोट, रायगढ़ा	120	166	286	2	2	2	2	240	332	एक्सप्रेस
30	जगदलपुर से सीनापाली व्हाया धरमगढ़, नवरंगपुर, आमपानी, जुनागढ़	195	21	216	2	2	2	2	390	42	साधारण
31	जरीगांव से जगदलपुर व्हाया अनवारी, चांदली	75	21	96	2	2	4	4	300	84	साधारण
32	जरीगांव से जगदपलपुर व्हाया चांदली	114	21	135	2	2	4	4	456	84	साधारण
33	झारसुगड़ा से कुनकुरी व्हाया पाली सांकरा, तपकरा	88	45	133	1	1	2	2	176	90	साधारण
34	झारसुगड़ा से रायपुर व्हाया सम्बलपुर, बरगढ़,लोहरचांटी, सरायपाली	145	181	326	1	1	1	1	145	181	एक्सप्रेस
35	झारसुगड़ा से जशपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुनकुरी	88	86	174	2	2	4	4	352	344	साधारण
36	जयपुर से जगदलपुर व्हाया चांदली	65	21	86	2	2	8	8	520	168	साधारण
37	जयपुर से जगदलपुर व्हाया	130	21	151	2	2	4	4	520	84	साधारण
38	जयपुर से रायपुर व्हाया जगदलपुर, कोटपाट, चांदली	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	जयपुर से रायपुर व्हाया नवरंगपुर, उमरकांट, कोण्डगांव	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	एक्सप्रेस
40	झारसुगड़ा से अम्बिकापुर व्हाया पत्थलगांव, लावाकेरा	88	200	288	2	2	2	2	176	400	एक्सप्रेस
41	झारसुगड़ा से चिरमिरी व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुनकुरी, पत्थलगांव	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	एक्सप्रेस
42	झारसुगड़ा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया सुन्दरगढ़, सबडेगा, पत्थलगांव, अम्बिकापुर	88	296	384	2	2	2	2	176	592	एक्सप्रेस
43	कंटाभांजी से रायपुर व्हाया नवपदा, महासमुन्द	230	109	339	2	2	2	2	460	218	एक्सप्रेस
44	खरियार से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द	180	109	289	2	2	2	2	360	218	एक्सप्रेस
45	कोण्डागांव से उमरकोट व्हाया रायघर	22	32	54	2	2	8	8	176	280	साधारण
46	कोरापुट से रायपुर व्हाया जयपुर, नरंगपुर, उमरकोट, दन्डसरा, कांकेर, धमतरी	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	एक्सप्रेस
47	कोरापुर से रायपुर व्हाया जयपुर, कोटपाट, चांदली, जगदुलपुर, कांकेर	90	222	312	4	4	4	4	360	1288	एक्सप्रेस
48	कुचीन्दा से रायगढ़ व्हाया ब्रजराजनगर, भीखमपाली, कनकतोरा, रेगारपाली	227	8	235	2	2	2	2	454	36	साधारण
49	लड्डूगांव से जगदलपुर व्हाया चांदली	105	21	126	1	1	2	2	210	42	साधारण
50	लिकमा से जगदलपुर व्हाया चांदली	85	21	106	2	2	4	4	340	84	साधारण
51	मलकानगिरी से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, कोटपाद, चांदली	220	21	241	2	2	2	2	440	42	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	मुखीगुड़ा से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियार	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	एक्सप्रेस
53	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, चांदली	60	80	140	2	2	4	4	240	320	साधारण
54	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया चांदली	115	105	220	2	2	4	4	460	420	साधारण
55	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया उमरकोट	165	58	223	2	2	4	4	660	232	साधारण
56	नरसिंगनाथ से रायपुर व्हाया नवपदा, खरियाररोड, महासमुन्द	104	107	211	2	2	4	4	416	428	साधारण
57	पद्मपुर से रायपुर व्हाया पैकमल, नवपदा, खरियाररोड	160	109	269	2	2	4	4	640	436	एक्सप्रेस
58	पारालाखेमुंडी से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, कोरापुट, जगदलपुर	340	150	490	2	2	2	2	680	300	एक्सप्रेस
59	पटनागढ़ से रायपुर व्हाया पद्मपुर, खरियार	248	200	448	2	2	2	2	496	400	एक्सप्रेस
60	फुलवानी से रायपुर व्हाया बलांगीर, बरगढ़, सरायपाली	290	181	471	2	2	2	2	580	362	एक्सप्रेस
61	पुरी से भिलाई व्हाया कटक, धनकानाल, संबलपुर, रायपुर	482	216	698	2	2	2	2	964	432	एक्सप्रेस
62	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धरमगढ़	80	299	379	2	2	2	2	160	598	एक्सप्रेस
63	राजनांदगांव से कांटाभांजी व्हाया रायपुर, महासमुन्द, खरियार	80	179	259	2	2	2	2	160	358	एक्सप्रेस
64	राउरकेला से कुनकुरी व्हाया राजगांगपुर, सुबडेगा, लावाकेरा, तपकरा	147	45	192	0	1	0	2	294	0	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	राउरकेला से अम्बिकापुर व्हाया सुबडेगा	147	270	417	2	2	2	2	294	540	एक्सप्रेस
66	राउरकेला से भिलाई व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	293	213	506	2	2	2	2	586	426	एक्सप्रेस
67	राउरकेला से जसपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, कुनकुरी	204	86	290	2	2	2	2	408	172	एक्सप्रेस
68	राउरकेला से रायगढ़ व्हाया बृजराजनगर, झारसुगड़ा	168	27	195	2	1	4	2	336	168	साधारण
69	राउरकेला से रायपुर व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	283	181	464	2	2	2	2	566	362	एक्सप्रेस
70	रायपुर से एरलागांव व्हाया रायघर, उमरकोट	73	186	259	2	2	2	2	146	372	एक्सप्रेस
71	राजाखरियार से रायपुर व्हाया महासमुन्द	185	109	294	2	2	2	2	370	218	एक्सप्रेस
72	संबलपुर से अम्बिकापुर व्हाया बरगढ़, पत्थलगांव	90	215	305	2	2	2	2	180	430	एक्सप्रेस
73	संबलपुर से कोरबा (बाल्को) व्हाया बरगढ़, लोहरछटी, सांरगढ़, चन्द्रपुर, शक्ति	90	175	265	2	2	2	2	180	350	एक्सप्रेस
74	संबलपुर से सांरगढ़ व्हाया बिरनापाली	80	80	160	2	2	4	4	320	320	साधारण
75	संबलपुर से रायपुर व्हाया बरगढ़, लोहरछटी	101	181	282	6	6	12	12	1212	2172	एक्सप्रेस
76	संबलपुर से बिलासपुर व्हाया शिवरीनारायण, सांरगढ़	164	239	403	4	4	4	4	656	956	एक्सप्रेस
77	संबलपुर से रायगढ़ व्हाया झारसुगड़ा, कनकतोरा	132	18	150	2	2	4	4	528	72	साधारण
78	सुन्दरगढ़ से रायगढ़ व्हाया गोपालपुर, तपारिया	72	24	96	1	1	2	2	144	48	साधारण
79	सुन्दरगढ़ से बिलासपुर व्हाया झारसुगड़ा, कनकतोरा, रायगढ़, सांरगढ़	105	108	213	2	2	2	2	210	360	एक्सप्रेस
80	उमरकोट से जगदलपुर व्हाया चांदली	126	21	147	2	2	4	4	504	84	साधारण
81	बरगढ़ से सारंगढ़ व्हाया रूसदा, सरिया	52	35	87	1	1	2	2	104	70	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	पुरी से रायपुर व्हाया भुवनेश्वर, सोनेपुर, बलांगीर, बरगढ़ सरायपाली	507	181	688	4	2	4	2	1014	724	एक्सप्रेस
83	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धरमगढ़	80	299	379	2	4	2	4	320	598	एक्सप्रेस
84	सम्बलपुर से रायगढ़ व्हाया भीमापाली, सारंगढ़	80	132	212	2	4	2	4	320	264	साधारण
85	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्डातरई, चिखली, चन्द्रपुर, बिरनापाली, सोहेलाबायपास	46	91	137	1	1	2	2	92	182	साधारण
86	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्डातरई, चन्द्रपुर, बरमकेला, भुक्ता, भटली	46	69	115	1	1	2	2	92	138	साधारण
87	रायपुर से राउरकेला व्हाया सरायपाली, सारंगढ़	168	269	437	2	4	2	4	672	538	एक्सप्रेस
88	कोरापुट से कांकेर व्हाया ज्योपुर, जगदलपुर	87	179	266	2	4	2	4	348	358	एक्सप्रेस
89	नवरंगपुर से कांकेर	115	58	173	4	2	4	2	230	232	साधारण
90	मलकानगिरी से जगदलपुर	169	21	190	6	2	6	2	338	126	साधारण
91	रायपुर से सोहेला व्हाया बंजारीनाका	8	200	208	1	4	1	4	32	200	साधारण
92	बिलासपुर से सम्बलपुर व्हाया सारंगढ़, सरायपाली	99	192	291	2	4	2	4	396	384	एक्सप्रेस
93	रायगढ़ से राउरकेला व्हाया झारसुगड़ा	138	27	165	6	2	6	2	276	162	साधारण
94	बसना से पदमपुर	21	21	42	4	4	8	8	168	168	साधारण
95	सरायपाली से पदमपुर	20	20	40	4	4	8	8	160	160	साधारण
96	मलकानगिरी से जगदलपुर व्हाया सुकुमा	135	25	160	4	4	8	8	1080	200	साधारण
97	झरीगांव से जगदलपुर व्हाया अनवारी	175	25	200	4	4	8	8	1400	200	साधारण
98	धमतरी से जगदलपुर व्हाया रायगढ़ा	200	25	225	4	4	8	8	1600	200	साधारण
99	जगदलपुर से सिनापाली व्हाया बेहरा, देवभोग	160	25	185	4	4	8	8	1280	200	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया कोसागुमुड़ा, अनवारी	65	85	150	4	4	8	8	520	680	साधारण
101	कालीमेला से जगदलपुर व्हाया सुकुमा, मलकानगिरी	65	25	90	4	4	8	8	520	200	साधारण
102	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया गिरला, कोटपाट, चांदली	50	25	75	4	4	8	8	400	200	साधारण
103	को८पाट से जगदलपुर	35	25	60	4	4	16	16	560	400	साधारण
104	राजनांदगांव से दामनजोड़ी व्हाया सोनाबेड़ा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	130	299	429	2	2	2	2	260	598	एक्सप्रेस
105	दुर्ग से मलकानगिरी व्हाया जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	165	240	405	2	2	2	2	330	480	एक्सप्रेस
106	कोंडागांव से उमरकोट व्हाया रायगढ़ा	45	80	125	2	2	4	4	180	320	साधारण
107	सम्बलपुर से भिलाई व्हाया लोहरचट्टी	105	230	335	2	2	4	4	420	920	एक्सप्रेस
108	बरगढ़ से सरायपाली व्हाया लोहरचट्टी	60	30	90	2	2	4	4	240	120	साधारण
109	दन्तेवाड़ा से मलकानगिरी व्हाया जगदलपुर, बोरीगुमा	160	60	220	2	2	4	4	640	240	साधारण
110	लड्डूगांव से जगदलपुर व्हाया नवरंगपुर, बोरीगुमा, चांदली	150	25	175	2	2	4	4	600	100	साधारण
111	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया पापहाण्डी, कोडींगा, कोसागुमुड़ा, अनवारी	90	25	115	2	2	4	4	360	100	साधारण
112	नवरंगपुर से भोपालपटनम	70	65	135	2	2	4	4	280	160	साधारण
113	कोसागुमुड़ा से जगदलपुर व्हाया अनवारी	90	65	155	2	2	4	4	360	260	साधारण
114	साडरेन्गा से जगदलपुर	85	35	120	2	2	4	4	340	140	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	जगदलपुर से मोटू व्हाया जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	280	25	305	2	2	4	4	1120	100	एक्सप्रेस
116	बेहरामपुर से जगदलपुर व्हाया केवीलाईन, रायगदा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	390	25	415	2	2	2	2	780	50	एक्सप्रेस
117	पारलखेमुंडी से जगदलपुर व्हाया रायगदा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	330	25	355	2	2	2	2	660	50	एक्सप्रेस
118	ज्योपटना से जगदलपुर व्हाया नवरंगपुर, चांदली	180	25	205	2	2	4	4	720	100	साधारण
119	भवानीपटना से दुर्ग	165	90	255	2	2	4	4	660	360	एक्सप्रेस
120	रायपुर से राजाखरियार	100	160	260	2	2	4	4	400	640	एक्सप्रेस
121	सरायपाली से बरगढ़	60	35	95	2	2	4	4	240	140	साधारण
122	ऐरलागांव से धमतरी	85	75	160	2	2	4	4	340	300	साधारण
123	झारसुगुड़ा से पाटलगांव व्हाया तुमला, कोटबा	60	75	135	2	2	4	4	240	300	साधारण
124	अंबिकापुर से पुरी व्हाया झारसुगुड़ा	404	250	654	2	2	2	2	808	500	एक्सप्रेस
125	बरगढ़ से सांकरा	57	80	137	2	2	4	4	228	320	साधारण
126	बरगढ़ से सिंघोड़ा व्हाया सरायपाली	57	50	107	2	2	4	4	228	200	साधारण
127	पूरी से कोरबा व्हाया झारसुगुड़ा, रायगढ़	425	300	725	2	2	2	2	850	600	एक्सप्रेस
128	नयागढ़ से रायपुर व्हाया चैचक, बंध, सोनपुर, बिनका, बरगढ़, सोहेला	277	181	458	2	2	2	2	554	362	एक्सप्रेस
129	झारसुगड़ा से पत्थलगांव व्हाया सबडेगा, तेलीझोर, तपकरा , कुनकुरी	85	86	174	2	2	4	4	352	344	साधारण

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक-एफ 5-58/दो/आठ-परि./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 15-07-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

REVISED DRAFT INTER STATE TRANSPORT RECIPROCAL AGREEMENT BETWEEN CHHATTISGARH AND ORISSA-PRELIMINARY NOTIFICATION.

Raipur, the 25th July 2008

No.-1632/STA/TC/08.—

(G.O.Rt. No. F-5-58/Two/Eight-Tra./2004, dated 25th August 2005.)

No. F-5-58/Two/Eight-Tra./2008.— dated 15-07-2008 Whereas, it is proposed to enter into an agreement between the States of Chhattisgarh and Orissa in respect of inter-state transport under section 88 of the Motor vehicle 1988 (No.59 of 1988)

Therefore, in supersession of the preliminary notification has already been published vide G.O.Rt. No. F-5-58/Two/Eight-Tra./2004, dated 25th August 2005 the following Revised Draft Reciprocal Inter-State Transport Agreement which the Government of Chhattisgarh proposes to enter with the Government of Orissa is hereby published for General Information of, all those who are likely to be affected as required by sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicle Act. 1988.

Notice is hereby given that the said Revised draft agreement will be taken up for consideration by the Principal Secretary for Home (Transport), Government of Chhattisgarh, Raipur after the expiry of thirty (30) days from the date publication of this notification in Chhattisgarh Gazette. Objections and suggesstions, if any, should be addressed in duplicate to the Principal Secretary to Government Home (Transport) Department, Government of Chhattisgarh, Raipur.

REVISED DRAFT AGREEMENT

Whereas, it is decided to control and regulate the plying of vehicles on inter-state routes between the States of Chhattisgarh and Andhra Pradesh It is hereby agreed to publish agreement on the following terms and conditions entered into by the States of Chhattisgarh and Andhra Pradesh.

1. Stage Carriage permits :-

(a) Unless there is anything repugnant to the subject or context, inter-state routes agreed for stage carriages shall mean the routes as agreed upon and number of trips and number of permits shall be as Annexure " A"

(b) A stage carriage of respective state shall pay motor vehicle taxes as per taxation Act of the respective state in respect of the portion falling in the state.

(c) The fares and freight chargeable by the operator in the reciprocating state shall be as approved by the countersigning Authority of that state. The tickets issued by the one state shall be valid in the reciprocating state.

(d) Till the substantive permits on the routes mentioned in the Annexure "A" here to are granted by the respective Transport Authorities, temporary permits to the nominees of the respective States shall be issued by the Transport Authorities of that State and shall be countersigned by the Transport Authorities of the reciprocating state.

The tax chargeable on temporary permits issued on the agreed routes within agreed trips shall be same as charged for substantive permits on the agreed routes.

(e) The Transport Authority of the reciprocating State may accord general concurrence under section 88 (7) of the said Act for issue of temporary permit as and when required.

(f) For the safety and convenience of passengers, the stage carriage shall not be allowed to ply on interstate routes, if, it is more then 10 years of age from the date of its initial registration.

(g) If any discrepancy is found in the distances of routes shown in the Annexure "A" the same shall be corrected through correspondence between the states and it shall not be treated as modification in the agreement.

(h) The permits in existence on the commencement of this agreement shall be deemed to be issued against the agreed routes in Annexure "A".

(i) In the total length of the route is more than 250 Km, the stage carriage shall be express.

(j) In case of a stage carriage two trips per day, the stage carriage shall start its journey from the home State and shall make night halt in the home State.

(k) On all inter state routes, the stage carriages of the home state shall have precedence in timings over the stage carriages of the reciprocating state.

2. **Contract Carriage operation of motor-cabs & maxi-cabs on Substantive permits:-**

The contract carriage permits for motor cab & maxi-cab snall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State with out any restriction on numbers. The motor-cab 7 maxi-cab shall pay the motor vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

3. **Contract Carriage operation of motor-cabs & maxi-cabs on Temporary Permits:-**

Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 may be issued for motor-cabs & maxi-cabs for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for single return trip for a specified inter-state route, connecting specified terminus without countersignature. The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permit so issued may be valid.

4. **Operation of Private Service Vehicles on Substantive Permits:-**

The permits for private service vehicle shall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating state without any restriction on numbers. The private service vehicle shall pay the motor vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

5. **Operation of Private Service Vehicles on Termporary Permits:-**

Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 may be issued for private service vehicles for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for a specified inter-state route, connecting specified terminus without countersignature. The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permits so issued may be valid.

6. **Goods Carriage Operation on Substantive Permits:-**

(a) The goods carriage permits of each State shall be countersigned by the Transport Authority of the other State in accordance with the provisions of sub-section 88 of the said Act without any restriction on the number of such permits.

(b) The vehicles shall not on their return Forney pick-up any goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating state for setting down such goods at any place or route in that State.

Provided that on the forward journey there shall be no restriction on setting down goods anywhere in the reciprocating State but no goods shall be picked up in that State.

(c) The goods carriages of respective State plying on substantive permit countersigned by State Transport Authority of reciprocating state shall be liable to pay tax Rs.6000/- for minimum one year in advance for which authorization shall be issued subject to validity of substantive primary permit. Both the States may revise this tax rate mutually as and when required. Tex due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the state Transport Authority of the reciprocating State along with a statement of permits issued.

(d) If the countersignature holders fail to pay tax due within 2 months from the date of expiry of the period for which the tax was last paid, the countersignature shall be demand to be

cancelled and if the owner appears for renewal of authorization, it may be allowed on payment of fine of Rs.1000/-.

(e) No countersignature on the permits shall be granted to a goods carriage which is 12 years old or more from the date of initial registration.

7. **Goods Carriage Operation on Temporary Permit:-**

Transport Authority of either State without prior concurrence of the reciprocating State shall issue any number of temporary permit for goods carriages. Temporary permit so issued shall be subject to the following conditions:-

(a) That the vehicle shall not be used for picking up and setting down goods between any two points lying exclusively within the jurisdiction of the reciprocating state.

(b) That the vehicle shall be liable to pay the motor vehicle tax in advance to the reciprocating state. Tax due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the State along with a statement o permits issued.

8. **General:-**

(a) The motor vehicle tax of the reciprocating state in respect of corridor (enclave portion as per second proviso to section 88(1) of M.V.Act. 1983) in reciprocating state shall be charged by the home state for the distance covered as per permit and no tax shall be charged by the reciprocating state in respect of the corridor for that distance.

(b) The reciprocating State shall accord recognition to tax payments, authorization, and conductor licenses for motor vehicles plying on the inter-state routes in accordance with this agreement.

(c) The vehicles owned by the Government of reciprocating State used for non-commercial purpose shall be totally exempted from payment of motor vehicles tax in the reciprocating State.

(d) The stage carriage shall be permitted to divert their service on inter-state routes specified in the agreement in case of construction of new road subject to the approval of concerned State Transport Authority.

(e) Each stage carriages shall carry a bilingual board written in Oriya and Hindi indicating terminus points of the inter-state route.

(f) Both the reciprocating states shall allow the stage carriages of the other state to take up and settle down the passengers from their respective notified bus terminals.

(g) This agreement shall remain in force until it is reviewed and a new agreement comes into force of until it is rescinded or modified by mutual consent on three months notice by either side.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Special Secretary.

OPENING OF NEW ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHHATTISGARH

ANNEXURE-A

No.	NAME OF ROUTES	Distance in Orissa	Distance in Chhattisgarh	Total Distance	No of Permits		No of Trips		Total kms Covered		Nature of Service
					Orissa	Chhattisgarh	Orissa	Chhattisgarh	Chhattisgarh in Orissa	Orissa in Chhattisgarh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aul to Bhilai via Chandikhol, Cuttack, Sambalpur & Sohela	472	209	681	2	2	2	2	944	418	Express
2	Bargarh to Bilaspur Via Saria, Sarangarh, Bhatgaon, Seorinarayan	120	159	279	2	2	2	2	240	318	Express
3	Bargarh to Korba Via Saria, Chandrapur Champa.	120	175	295	1	2	1	2	240	175	Express
4	Bargarh to Raigarh Via Bhatli, Nuapada, Chandrapur	92	87	179	4	4	8	8	736	696	Ordinary
5	Bargarh to Raipur Via Sohela, Saria	46	181	227	1	2	2	4	184	362	Ordinary
6	Bargarh to Raigarh Via Sarangarh, Ruchida, Saria	52	87	139	2	2	4	4	208	348	Ordinary
7	Bargarh to Shakti Via Saria, Chandrapur, Khariyar.	76	120	196	2	2	4	4	304	480	Ordinary
8	Baripada to Raipur Via Keonjhar, Smbalpur, Luharchati	355	181	536	2	2	2	2	710	362	Express
9	Barpali to Raipur Via Bargarh, Luharchati, Basna, Aranga.	128	181	309	2	2	2	2	256	362	Express
10	Belpahad to Ambikapur Via Raigarh	45	214	259	2	2	2	2	90	428	Express
11	Berhampur to Bailadiila Via Jaypore, Jagdalpur	404	150	554	2	2	2	2	808	300	Express
12	Berhampur to Raipur Via Bhawanipatna, Khariyar Road, Mahasamund, Arang	473	[illegible]	582	4	2	4	2	946	436	Express
13	Bhawanipatna to Jagdalpur Via Junagarh, Nawrangpur, Kotpad, Chandili	384	[illegible]	406	2	2	2	2	768	44	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Bhawanipatna to Raipur Via Dharamgarh, Deobhog	80	229	309	2	2	2	2	160	458	Express,
15	Bhikampali to Sana (Astha) Via Kanaktora, Raigarh, Pathalgao, Kunkuri	36	199	235	2	2	4	4	144	796	Ordinary
16	Bhubaneswar to Bhilai Via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Luharchati	422	209	631	2	2	2	2	844	418	Express
17	Bhadrak to Raipur Via Keonjhar, Loharchati	400	181	581	2	0	2	0	0	362	Express
18	Bhubaneswar to Durg via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Bargarh	422	235	657	2	0	2	0	0	470	Express
19	Bilaspur to Berhampur Via Raipur, Mahasamund, Bhawanipatna	338	227	565	2	2	2	2	676	454	Express
20	Bolangir to Raipur Via Bargarh, Sohela, Saraipali	195	181	376	2	2	2	2	390	362	Express
21	Bhawanipatna to Raipur Via Khariar	130	109	239	2	2	2	2	260	218	Ordinary
22	Bhawanipatna to Durg Via Khariar, Raipur	130	149	279	2	2	2	2	260	298	Express
23	Damanjodi to Jagdalpur Via Boriguma.	121	60	181	2	1	4	2	242	240	Ordinary
24	Damanjodi to Jagdalpur Via Chandili	121	21	142	2	2	4	4	484	84	Ordinary
25	Damanjodi to Raipur Via Koraput, Jeypore, Boriguma, Dhanpunjee,	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	Express
26	Damanjodi to Raipur Via Sunabeda, Korapur, Jeypore, Umarkot.	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	Express
27	Dharamgarh to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar Road, Mahasamund, Arang.	205	109	314	4	4	4	4	820	436	Express
28	Hatibandha to Raipur Via Khariar Road	115	109	224	2	2	4	4	460	436	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Jagdalpur to Dhamtari Via Karpawand, Sinsari, Umarkot, Raygada.	120	166	286	2	2	2	2	240	332	Express
30	Jagdalpur to Sinapali Via Dharamgarh, Nawrangpur, Ampani, Junagarh	195	21	216	2	2	2	2	390	42	Ordinary
31	Jarigaon to Jagdalpur Via Anwari, Chandili.	75	21	96	2	2	4	4	300	84	Ordinary
32	Jarigaon to Jagdalpur Via Chandili.	114	21	135	2	2	4	4	456	84	Ordinary
33	Jharsuguda to Kunkuri Via Balisankara, Tapkara.	88	45	133	1	1	2	2	176	90	Ordinary
34	Jharsuguda to Raipur Via Sambalpur, Bargarh, Loharchati, Saraipali	145	181	326	1	1	1	1	145	181	Express
35	Jharsuguda to Jaspurnagar Via Sundergarah, Telijore, Taparia, Kunkuri	88	86	174	2	2	4	4	352	344	Ordinary
36	Jeypore to Jagdalpur Via Chandli	65	21	86	2	2	8	8	520	168	Ordinary
37	Jeypore to Jagdalpur	130	21	151	2	2	4	4	520	84	Ordinary
38	Jeypore to Raipur Via Jagdalpur, Kotpad, Chandili	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	Express
39	Jeypore to Raipur Via Nawrangpur, Umarkot, Kondagaon	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	Express
40	Jharsuguda to Ambikapur Via Pathalgaon, Lawakera	88	200	288	2	2	2	2	176	400	Express
41	Jharsuguda to Chirimiri Via Sundardarh, Telijore, Tapkara, Kunkuri, Pathalgaon	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	Express
42	Jharsuguda to Manendragarh via Sundargarh, Subdega, Pathalgaon, Ambikapur	88	296	384	2	2	2	2	176	592	Express
43	Kantabanji to Raipur Via Nunapada,Mahasamund	230	109	339	2	2	2	2	460	218	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Khariar to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar Road, Mahasamund	180	109	289	2	2	2	2	360	218	Express
45	Kondagaon to Umarkot via Raighar	22	35	57	2	2	8	8	176	280	Ordinary
46	Koraput to Raipur via Jeypore, Nawarangpur, Umarkot Dansara, kanker, Dhamtari	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	Express
47	Korapur to Raipur via Jeypore, Kotpad, chandili, Jagdalpur, Kanker	90	322	412	4	4	4	4	360	1288	Express
48	Kuchinda to Raigarh via Brajrajnagar, Bhikampali, Kanaktora, Rengarpali,	227	18	245	2	2	2	2	454	36	Ordinary
49	Ladugaon to Jagdalpur Via Chandili	105	21	126	1	1	2	2	210	42	Ordinary
50	Likma to Jagdalpur Via Chandili	85	21	106	2	2	4	4	340	84	Ordinary
51	Malkangiri to Jagdalpur Via Jeypore, Kotpad, Chandili	220	21	241	2	2	2	2	440	42	Ordinary
52	Mukhiguda to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	Express
53	Nawrangpur to Jagdalpur Via Jeypore, Chandili	60	80	140	2	2	4	4	240	320	Ordinary
54	Nawrangpur to Kanker Via Chandili	115	105	220	2	2	4	4	460	420	Ordinary
55	Nawrangpur to Kanker Via Umerkote	165	58	223	2	2	4	4	660	232	Ordinary
56	Narsinghnath to Raipur Via Nuapada Khariar Road, Mahasamund	104	107	211	2	2	4	4	416	428	Ordinary
57	Padampur to Raipur Via Paikmal, Nuapada, Khariar Road	160	109	269	2	2	4	4	640	436	Express
58	Paralakhemundi to Bailadila Via Jeypore Koraput, Jagdalpur.	340	150	490	2	2	2	2	680	300	Express
59	Patnagarh to Raipur via Padampur, Khariar	248	200	448	2	2	2	2	496	400	Express
60	Phulbani to Raipur Via Bolangir, Bargarh, Saraipali.	290	181	471	2	2	2	2	580	362	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Puri to Bhilai Via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Luharchati, Raipur.	482	216	698	2	2	2	2	964	432	Express
62	Rajnandgaon to Bhawanipatana Via Raipur, Gariyaband, Deobhog, Dharamgarh	80	299	379	2	2	2	2	160	598	Express
63	Rajnandgaon to Kantabanji Via Raipur, Mahasamund, Khariar	80	179	259	2	2	2	2	160	358	Express
64	Rourkela to Kunkuri Via Rajgangpur,Subdega, Lawakera, Tapkara	147	45	192	0	1	0	2	294	0	Ordinary
65	Rourkela to Ambikapur Via Subdega	147	270	417	2	2	2	2	294	540	Express
66	Rourkela to Bhailai Via Sambalpur, Luharchati.	293	213	506	2	2	2	2	586	426	Express
67	Rourkela to Jaspurnagar Via Sundargarh, Telijore, Kunkuri	204	86	290	2	2	2	2	408	172	Express
68	Rourkela to Raigarh Via Brajrajnagar, Jharsuguda	168	27	195	2	1	4	2	336	108	Ordinary
69	Rourkela to Raipur Via Sambalpur, Loharchatti	283	181	464	2	2	2	2	566	362	Express
70	Raipur to Erlagaon Via Raighar, Umerkote	73	186	259	2	2	2	2	146	372	Express
71	Rajakhariar to Raipur Via Mahasamund	185	109	294	2	2	2	2	370	218	Express
72	Sambalpur to Ambikapur Via Bargarh, Pathalgon	90	215	305	2	2	2	2	180	430	Express
73	Sambalpur to Korba (Balko) Via Bargarh, Luharchati, Sarangarh, Chandarpur, Shakti	90	175	265	2	2	2	2	180	350	Express
74	Sambalpur to Sarangarh Via Birnapali	80	80	160	2	2	4	4	320	320	Ordinary
75	Sambalpur to Raipur Via Bargarh, Luharchatti	101	181	282	6	6	12	12	1212	2172	Express
76	Sambalpur to Bilaspur Via Seorinarayan, Sarangarh	164	239	403	4	4	4	4	656	956	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Sambalpur to Raigarh Via Jharsuduga, Kananktora	132	18	150	2	2	4	4	528	72	Ordinary
78	Sudargarh to Raigarh Via Gopalpur, Taparia	72	24	96	1	1	2	2	144	48	Ordinary
79	Sundargarh to Bilaspur Via Jharsuguda, Kanktora, Raigarh, Sarangarh	105	180	285	2	2	2	2	210	360	Express
80	Umerkote to Jagdalpur Via Chandili	126	21	147	2	2	4	4	504	84	Ordinary
81	Bargarh to Sarangarh Via Ruchida, Saria	52	35	87	1	1	2	2	104	70	Ordinary
82	Puri to Raipur Via Bhubneshwar, Sonepur, Balangir, Bargarh, saripali	507	181	688	4	2	4	2	1014	724	Express
83	Rajnandgaon to Bhawanipatana Via Raipur, Gariyaband, Deobhog, Dharamgarh	80	299	379	2	4	2	4	320	598	Express
84	Sambalpur to Raigarh Via Bhimapali, Sarangarh	80	132	212	2	4	2	4	320	264	Ordinary
85	Raigarh to Bargarh Via Kondatarai, Chikhili, Chandrapur, Birnapali, Sohela by pass	46	91	137	1	1	2	2	92	182	Ordinary
86	Raigarh to Bargarh Via Kondatarai, Chandrapur, Baramkela, Bhukta, Bhathly	46	69	115	1	1	2	2	92	138	Ordinary
87	Raipur to Raurkela Via Saripali,Sarangarh	168	269	437	2	4	2	4	672	538	Express
88	Koraput to Kanker Via Jeoypur, Jagdalpur	87	179	266	2	4	2	4	348	358	Express
89	Nawrangpur to Kanker	115	58	173	4	2	4	2	230	232	Ordinary
90	Malkangiri to Jagdalpur	169	21	190	6	2	6	2	338	126	Ordinary
91	Raipur to Sohela Via Banjarinaka	8	200	208	1	4	1	4	32	200	Ordinary
92	Bilaspur to Sambalpur Via Sarangarh,Saripali	99	192	291	2	4	2	4	396	384	Express
93	Raigarh to Raurkela Via Jharsuguda	138	27	165	6	2	6	2	276	162	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Basna to Padampur	21	21	42	4	4	8	8	168	168	Ordinary
95	Saripali to Padampur	20	20	40	4	4	8	8	160	160	Ordinary
96	Malkangiri to Jadalpur Via Sukuma	135	25	160	4	4	8	8	1080	200	Ordinary
97	Jharigaon to Jadalpur Via Anwari	175	25	200	4	4	8	8	1400	200	Ordinary
98	Dhamtari to Jagdalpur Via Raighar	200	25	225	4	4	8	8	1600	200	Ordinary
99	Jagdalpur to Sinapali Via Behra, Deobhog	160	25	185	4	4	8	8	1280	200	Ordinary
100	Nawrangpur to Jagdalpur Via Kosagumuda, Anwari	65	85	150	4	4	8	8	520	680	Ordinary
101	Kalimela to Jagdalpur Via Sukuma, Malkangiri	65	25	90	4	4	8	8	520	200	Ordinary
102	Nawrangpur to Jagdalpur Via Girla, Kotpad and Chandil	50	25	75	4	4	8	8	400	200	Ordinary
103	Kotpad to Jagdalpur	35	25	60	4	4	16	16	560	400	Ordinary
104	Rajnandgaon to Damanjodi Via Sunabeda, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	130	299	429	2	2	2	2	260	598	Express
105	Durg to Malkangiri Via Jeypore, Boriguma & Chandil	165	240	405	2	2	2	2	330	480	Express
106	Kondagaon to Umerkot Via Righar	45	80	125	2	2	4	4	180	320	Ordinary
107	Sambalpur to Bhilai Via Loharchati	105	230	335	2	2	4	4	420	920	Express
108	Bargarh to Saraipali Via Loharchati	60	30	90	2	2	4	4	240	120	Ordinary
109	Dantewada to Malkangiri Via Jagdalpur, Boriguma	160	60	220	2	2	4	4	640	240	Ordinary
110	Ladugaon to Jagdalpur Via Nawrangpur, Boriguma & Chandil	150	25	175	2	2	4	4	600	100	Ordinary
111	Nawrangpur to Jagdalpur Via Papadahandi, Kodinga, Kosagumuda, Anwari	90	25	115	2	2	4	4	360	100	Ordinary
112	Nawrangpur to Bhopalpatnam	70	65	135	2	2	4	4	280	160	Ordinary
113	Kosagumuda to Jagdalpur Via Anwari	90	65	155	2	2	4	4	360	260	Ordinary
114	Sodrenga to Jagdalpur	85	35	120	2	2	4	4	340	140	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Jagdalpur to Motu Via Jeypore, Boriguma, Chandil	280	25	305	2	2	4	4	1120	100	Express
116	Berhampur to Jagdalpur Via KV line, Rayagada, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	390	25	415	2	2	2	2	780	50	Express
117	Paralakhemundi to Jagdalpur Via Rayagada, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	330	25	355	2	2	2	2	660	50	Express
118	Joypatna to Jagdalpur Via Nawrangpur, Chandil	180	25	205	2	2	4	4	720	100	Ordinary
119	Bhawanipatna to Durg	165	90	255	2	2	4	4	660	360	Express
120	Raipur to Rajkhariar	100	160	260	2	2	4	4	400	640	Express
121	Saraipali to Bargarh	60	35	95	2	2	4	4	240	140	Ordinary
122	Erlagaon to Dhamtari	85	75	160	2	2	4	4	340	300	Ordinary
123	Jharsuguda to Patalgaon Via Tumala, Kotba	60	75	135	2	2	4	4	240	300	Ordinary
124	Ambikapur to Puri Via Jharsuguda	404	250	654	2	2	2	2	808	500	Express
125	Bargarh to Sankra	57	50	137	2	2	4	4	228	320	Ordinary
126	Bargarh to Shqaud Via Saraipali	57	50	107	2	2	4	4	228	200	Ordinary
127	Puri to Korba Via Jharsuguda, Raigarh	425	300	725	2	2	2	2	850	600	Express
128	Nayagarh to Raipur Via Chaichhak, Boudh, Sonpur, Binka, Bargarh, Sohella	277	181	458	2	2	2	2	554	362	Express
129	Jharsuguda to Patalgaon Via Subdergarh, Telijore, Tapkera, Kunkuri	85	86	174	2	2	4	4	352	344	Ordinary

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक 1050/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 14	2.68	अनुविभागीय अधिकारी, माण्ड नहर अनुविभाग क्र. 1, खरसिया.	साराडीह माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक 1051/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	राधोपुर प.ह.नं. 19	2.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोविन्दपुर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	जाटम प.ह.नं. 58	0.10	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	डोंगाम जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक/08/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नगधा	4.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	परसदा जलाशय योजना में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक/09/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	खैरी	2.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	टेंगना व्यपवर्तन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2008

प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	महराजपुर प. ह. नं. 22	0.963	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मैनपुरी जलाशय में डुबान में अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2008

प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मैनपुरी प. ह. नं. 23	5.697	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मैनपुरी जलाशय के विस्तारीकरण में डुबान, बांध पार एवं नहर में.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2008

प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	दरिया प. ह. नं. 46	1.583	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	समनापुर जलाशय में नहर में अर्जित भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नवापारा	4.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	नवापारा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	कुटेलामुड़ा	1.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	साजाबहरी	1.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	चैतमा	9.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 11/क/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	अमलडीहा प. ह. नं. 7	0.266	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	नवापारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	पूंजीपथरा प. ह. नं. 34	8.161	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़	मेसर्स रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज लि. यूनिट-2 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7369/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बिड़ौरी प. ह. नं. 29	0.125	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण/सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	जालबांधा, बिड़ौरी, मड़ौदा मार्ग के कि. मी. 6/6 पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंच निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7370/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	शेरगढ़ प. ह. नं. 33	1.239	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण/सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	शेरगढ़ बफरा मार्ग पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंच निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7371/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मड़ौदा प. ह. नं. 29	0.237	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण/सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	जालबांधा, बिड़ौरी, मड़ौदा मार्ग के कि. मी. 6/6 पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंच निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 जुलाई 2008

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- **(क) जिला-सरगुजा**
- **(ख) तहसील-शंकरगढ़**
- **(ग) नगर/ग्राम-पहरी, प. ह. नं. 1**
- **(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.816 हेक्टेयर**

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
407	1.400
408	0.603
413	1.150
409	0.444
410	2.023
412	0.323
411	1.353
415	1.600
417	1.120
418	0.110
419	0.540

	(1)	(2)
	404	0.150
योग	12	10.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुघरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक/ 6 अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	113/1	0.012
	113/2	0.004
योग	2	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तान्दुला नदी पुल एवं पहुंच मार्ग में अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक/ 7 अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-बालोद, प. ह. नं. 5/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1192/2	0.016
	1193	0.052
योग	2	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तान्दुला नदी पुल एवं पहुंच मार्ग में अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 जुलाई 2008

क्रमांक/ 5 अ-82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-बालोद, प. ह. नं. 5/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1048/5	0.048
	1048/5	0.032
योग	2	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा फीडर नहर में अर्जित भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/04/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-अमाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
681	0.63
682	0.81
680	0.03
679/1	0.58
650/1	0.29
679/4, 5, 6	1.45
648/1	0.13
643/1	0.13
1663/1	0.08
649/1	0.31
647	0.03
649/2	0.05
643/3, 5	0.55
643/2, 4	0.46
656	0.40
657, 658/6	0.41
658/2	0.69
640	0.04
610/3	0.47
596/1	0.11
592/3	0.19
612/2	0.09
554	0.26
609/2	0.05
609/1	0.13
596/2	0.51
591/2	0.05
591/1	0.11
589/1	0.32
589/6	0.36
556/1	0.11
556/2	0.12
589/2	0.25
597	0.32
538/1	0.67
564	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
496	0.06	821/2	0.16
562	0.26	819	0.27
538/2	0.16	821/1	0.10
539	0.04	820/3	0.31
535, 536	0.38	820/2	0.33
533/1	0.19	817/1	0.12
534	0.21	1808	1.28
533/2	0.09	1683	0.49
532/2	0.13	1681	0.68
531	0.01	1809	0.61
512/2	0.41	1810/1	0.08
515/1	0.09	1811	0.07
414	0.14	1904	0.19
513	0.08	1812	0.62
492	1.24	1822	0.01
493	0.21	1827	0.37
495/2	0.19	1626	0.36
488/1	0.11	1813	0.02
488/5	0.02	1821	0.73
448/1	0.08	1820	0.39
488/2	0.20	1825	0.39
449/1	0.09	1826	0.35
447	0.20	1887/1, 1888/1	0.05
444	0.63	1828	0.19
441	0.54	1785	1.08
439	0.19	1787/2	0.16
440	0.10	1784	0.18
438	0.04	1782	0.12
792/2	0.56	1589	0.19
1667/2	1.26	1590	0.47
792/1	0.65	1625	0.16
1678	0.16	1624	0.35
1677	0.24	1622	0.21
1675	0.67	1621	0.10
1667/1	0.38	1620	0.35
794, 796	0.88	1638	0.82
818/2	0.37	1640	0.09
818/1	0.07	1665	0.12
821/3	0.10	1663/2	0.07
821/7	0.15	1662/2	0.19
1680	0.12	1657/7	0.07
1679/2	0.28	1657/1	0.37
1654	0.47	1664	0.81

(1)	(2)
1657/5	1.32
योग	39.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तमता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.728 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	0.120
185	0.061
186/3	0.080
221	0.172
228	0.057
226	0.097
238	0.020
399/1 क	0.040
392/1 क	0.073
373/5	0.081
373/7	0.255
383/1	0.138
376/2 क	0.101
373/1 ख	0.057
365	0.150
361/2 क, 262/2 क, 363/2 क	0.085
378/1 ग	0.068
378/1 च	0.073
योग 18	1.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चंदागढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185/2 ख	0.081
202	0.069

	(1)	(2)
	203/11	0.081
	37/1 ख	0.283
	38/2	0.081
	77/1	0.020
योग	6	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	258/1 ग	0.061
	258/1 ख 1	0.101
	909	0.171
योग	3	0.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुड़केल खजरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.585 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	245/5 ग	0.040
	243	0.101
	263/2	0.061
	285	0.040
	280/1 घ	0.080
	305	0.101
	300/1 ख	0.081
	342/7	0.081
योग	8	0.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-बालाझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.715 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	49/1	0.121
	10/5 ख	0.163
	9/3	0.040
	7/7	0.405
	10/3	1.052
	10/5 क	0.405
	9/2 ख	0.259
	9/2 क	0.146
	64/6 क	1.307
	64/21	0.628
	76/2	0.097
	65/5	1.254
	74/2	0.413
	8/2	0.202
	76/7	0.061
	95/3	0.081
	96/3	0.081
योग	17	6.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तमता जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7365/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-जोम, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.30 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
898	0.17
900	0.13
901	0.05
928	0.14
929	0.30
931	0.16
932	0.18
940/1	0.18
942	0.60
966/1	0.09
966/3	0.36
967/1	0.16
967/2	0.04
968	0.18
969	0.09
988	0.06
989/2	0.23

(1)	(2)
989/3	0.18
योग 18	3.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7366/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-उदान, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
7	0.06
8/1	0.33
8/2	0.18
8/4	0.19
8/5	0.20
8/7	0.44
9/2	0.01
12	0.08
13/2	0.26
योग 9	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7367/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-तेंदूभाठा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.69 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5	0.25
6	0.14
7	0.09
8	0.16
24	0.20
25/1	0.04
25/2	0.04
30	0.04
31	0.11
32	0.09
63/1	0.20
65	0.23
68	0.05

(1)	(2)
69	0.11
71/1	0.15
82	0.03
86	0.31
87	0.38
95/1	0.45
95/2	0.21
96/2	0.20
96/4, 5, 6, 7	0.24
96/8, 9, 10, 11	0.20
96/12	0.27
96/13, 14, 15	0.19
96/17	0.26
96/20	0.50
96/23	0.23
96/24	0.06
98	0.26
योग 30	5.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जुलाई 2008

क्रमांक/7368/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-सण्डी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
133/6	0.32
187/1	0.10
183/2	0.20
190/2	0.13
185	0.10
योग	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत उलट कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्रमांक/7566/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरमुड़ा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.21 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
652/1	0.06
652/2	0.05
680	0.11
681	0.24
687	0.48

(1)	(2)	(1)	(2)
653	0.24	664	0.32
656	0.34	670	0.17
654	0.12	671	0.10
657/1	0.12	673	0.11
682	0.28	676	0.23
683	0.08	684	0.11
657/2	0.12	686	0.51
700	0.57	688	1.13
655	0.25	689	0.36
679	0.06	690	0.29
685	0.21	693	0.28
620/1	0.36	691	0.02
703	0.23	692	0.31
704/2	0.12	694	0.28
705/2	0.18	695/1	0.38
620/2	0.36	695/2	0.13
698	0.29	695/3	0.27
704/1	0.20	696	0.50
705/4	0.17	697	0.33
701	0.21	699	0.30
621	0.12	702	0.40
661	0.17	705/1	0.35
622	0.34	705/3	0.05
623	0.40	706	0.19
624	0.28		
642	0.19	योग 65	17.21
674	0.42		
625	0.39		
669	0.14		
626	0.23		
665	0.11		
672	0.10		
643	0.20		
662	0.59		
675	0.52		
663	0.44		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डुबान क्षेत्र में अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 7481/अधीक्षक/2008.—सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का आदेश क्रमांक/बी-1-30/2007/4/एक, रायपुर दिनांक 02-06-2008 द्वारा श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा को राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी प्रदान की गई है जिसके फलस्वरूप

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1986/अधीक्षक/2008 कोरबा, दिनांक 19-02-2008 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है :—

1. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**

1. अपर कलेक्टर (नजूल)
2. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतनवृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
3. नोडल अधिकारी (खाद्य शाखा)
4. नगर सेना
5. पासपोर्ट

प्रभारी अधिकारी

1. लाइसेंस
2. भू-अर्जन/भूमि बंटन
3. सांख्य लिपिक

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

2. **श्री आर. एक्का, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर, सत्कार अधिकारी**

प्रभारी अधिकारी

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य)
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय)

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

3. **श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला जनगणना अधिकारी
2. भाड़ा नियंत्रक अधिकारी
3. नजूल अधिकारी
4. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन
5. सहायक अधीक्षक सामान्य
   (पुरातत्व एवं पर्यटन, आर. बी. सी. के प्रकरण, सालेशियम फंड/संजीवनी)
6. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम

7. आपदा एवं राहत शाखा

8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

9. दंगा पीड़ित 1984

10. कम्प्यूटर शाखा

11. नवोदय विद्यालय

12. सिटीजन हेल्प लाईन

13. जिला शहरी विकास अभिकरण

14. 20 सूत्रीय कार्यक्रम

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

4. **सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला नाजिर

2. प्रतिलिपि शाखा

3. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण

4. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल

5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स

6. आवक-जावक

7. वरिष्ठ लिपिक/अति. वरिष्ठ लिपिक

8. राजस्व मोहर्रिर

9. सहायक अधीक्षक राजस्व

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट**

प्रभारी अधिकारी

1. भू-अभिलेख

2. व्यवहारवाद

3. राजस्व आंकिक

4. अल्प बचत

5. पर्यावरण शाखा

6. सूचना का अधिकार

7. सहायक अधीक्षक विविध

8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

9. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच ,

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

6. **श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. वाचक कलेक्टर
2. वित्त एवं स्थापना
3. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
4. जनदर्शन/जनसंपर्क
5. विशेष कक्ष
6. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

7. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**

1. **राजस्व**

   1. अनुविभागीय अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण.अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

8. **श्रीमती आर. संगीता, आई. ए. एस./अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा एवं पाली तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा एवं पाली तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फ़सल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर
2.	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर
4.	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
5.	श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर
7.	श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
8.	श्रीमती आर. संगीता, आई. ए. एस.	श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय)
रजिस्ट्रार कार्यालय—शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

नामनिर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन

क्रमांक-01/निर्वाचन/नानितिप्र/1764-66.—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के तहत नामनिर्देशन-पत्रों को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2008, समय 12 बजे मध्यान्ह तक अध्यक्ष द्वारा नियत किया गया है. नामनिर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 20 अगस्त 2008 को की जावेगी.

अत: छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि नामनिर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जा रहा है.

टिप्पणी :- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में अन्तर्विष्ट चिकित्सा व्यवसायी द्वितीय बोर्ड के गठन हेतु मतदान के लिए अर्ह हैं तथा नाम-निर्देशन की पात्रता रखते हैं.

रक्षपाल गुप्ता,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक-एफ/134/न. पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2008/1076.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के उप-निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	21, 22	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 "क"	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	04-08-08 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
2.	नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	11-08-08 सोमवार
3.	नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	12-08-08 मंगलवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	14-08-08 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	14-08-08 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	26-08-08 मंगलवार प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	28-08-08 गुरुवार प्रात: 9.00 बजे से

परिशिष्ट-2

नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-जून 2008 की स्थिति में

क्र.	जिला	नगरपालिका	रिक्त पद		
			अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरगुजा	नगर पंचायत, राजपुर	अध्यक्ष	-	-
2.	दुर्ग	नगर पंचायत, नवागढ़	अध्यक्ष	-	-
3.	—,,—	नगर पंचायत, गुण्डरदेही	अध्यक्ष	-	-
		योग	3	-	-

परिशिष्ट–1

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2008

क्रमांक/एफ–134/न. पा./रानिआ/निर्वा. कार्यक्रम/2008/1078.—नगर पंचायत कुसमी, जिला–सरगुजा के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु निर्वाचन–2008 समय अनुसूची (कार्यक्रम) —

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75–ग 75–घ	04-08-08	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75–ङ	04-08-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रतीकों का आवंटन	75–च 75–छ	04-08-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
4.	मतदान	75–ग (एक)	26-08-08	मंगलवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
5.	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75–ग (दो) 75–ज	28-08-08	गुरुवार	प्रात: 9.00 बजे से

परिशिष्ट–2

नगर पंचायत अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए मतदान

क्र.	जिला	नगर पालिका	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरगुजा	नगर पंचायत, कुसमी	अध्यक्ष वापस बुलाना

आर. के. साहू,
उप–सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th July 2008

No. 780/Confdl./2008/II-1-1/2001.—Hon'ble Shri Justice L. C. Bhadoo, Judge, High Court of Chhattisgarh, has relinquished charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 24-07-2008 in the afternoon on attaining the age of 62 years.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.

Bilaspur, the 22nd July 2008

No. 25/L.G./2008/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Bakshi, Presently posted as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 31-0[illegible]2008 to 08-08-2008.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Bakshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

क्रमांक 136/दो-2-24/2003.— श्री एम. आर. गुरुपंच, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अम्बिकापुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-03-2008 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2007

क्रमांक 41/निर्वा. याचिका/06/1704.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. 82/छ. ग.-वि. स./11/2004/3591 दिनांक 18 जुलाई, 2007 निर्वाचन अर्जी संख्या 07/04 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 17 जुलाई, 2007—26 आषाढ़, 1929 (शक)

अधिसूचना

सं 82/छ. ग.-वि. स. /07/2004.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग वर्ष 2004 की निर्वाचन अर्जी संख्या 07 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर बेंच के तारीख 05-10-06 के आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Election Petition No. 07/2004

PETITIONER - Naresh Kumar Patel s/o Shri Goverdhan Prashad, Aged about 35 years, Occu.- Agriculture, Resi. of Dhanagar, Tah. & Distt. Raigarh (C. G.).

VERSUS

RESPONDENTS -

1. Shri Nand Kumar Patel s/o Late Mahendra Singh Patel, Aged about 49 years, Resi. of Post Nandeli, Tah. & Distt. Raigarh (C. G.), Assembly Constituency, Kharsia.

2. Laxmi Prasad Patel s/o Late Doulat Ram Patel, Aged about 62 years, Resi. of Village Chhuhipali, Post- Patel Pali, Distt. Raigarh (C. G.).

3. Vishnu Tiwari s/o Late Shatrudhan Tiwari, Aged about 55 years, Resi. of Village Telicote, Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

4. Bhaiyalal s/o not khown, Aged about 50 years, Gorepar, Tah.-Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

5. Ujagar Lal Verma s/o not known, P. O. Botalda, Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.)

6. Shant Kumar s/o Salikram, Aged About 52 years, Resi. of Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

7. Harilal Patel s/o not konwn, Aged about 53 years, Resi. of Village & Post Nagoi., Tah. Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

ELECTION PETITION No. 07/2004

Naresh Kumar Patel

Versus

Shri Nand Kumar Patel & others

Present : Smt. Hameeda Siddiqui, Adv. for the petitioner.

Shri B. P. Sharma, Adv. for the respondent No. 1.

Shri M. K.Bhaduri, Adv. for the respondent No. 4

Shri B. P. Gupta, Adv. for the respondent No. 7

ORDER

Per Dhirendra Mishra, J.

This order shall dispose of I. A. No. 2564/2006 filed by respondent No. 1, an application under order 7 Rule 11 of C.P.C. and I. A. No.2685/2006 filed by respondent No.7 under Order 7 Rule 11 of C. P. C. for dismissing the election petition in *limine* for non-compliance of the mandatory requirement of Representation of People's Act, 1951 and the rules made thereunder (hereinafter referred to as the Act of 1951 and Rules).

2. The petitioner being registered as Electoral in 18, Kharsia Assembly Constituency has filed this Election Petition under Section 80 and 80 A of the Act of 1951 for declaring the election of respondent No. 1 as a Member of Legislative Assembly from Constituency No. 18, Kharsia, district Raigarh as illegal and void on the ground that he resorted to the corrupt practices during the election as contemplated in Sub-section 1, 5 and 7 of Section 123 of the Act of 1951. The detail election programme is given in paragraph 2 of the petition and the respondent No.1 was declared elected by a margin of 32,768 votes from the respondent No. 2 on the election counting which was held on 4-12-2003.

3. The respondent No. 1 has filed the above application and has prayed for dismissal of the petition at the threshold on the ground that the material fact and material particulars relating to the alleged corrupt practices averred in para 10 (a) to 10 (j) of the petition do not disclose cause of action and the allegations and particulars are not pleaded and the petition is bereft of material facts/ material particulars. Apart from the above, the respondent No. 1 has aslo taken a ground that the verification contained in affidavit does not conform to the Form prescribed under the law.

4. Similarly, the sum and substance of the application preferred by the respondent No. 7 is that the election petition do not accompany with as many true copies as per Section 81 (3) of the Act of 1951 and copy of the petition supplied to the respondent was not the true copy of the petition as the copy supplied to the respondent does not bear the signature of the petitioner nor it does contain the verification. The verification and affidavit supplied to the respondent does not contain the signature of the petitioner and the copies supplied to the respondent which is accompanied by affidavit does not contain the seal and signature of the oath commissioner and thus there is a total non-compliance of the mandatory provisions of Section 81 (3) of the Act of 1951 and for this reason, it deserves to be dismissed. A further objection is that the petition does not include the statement naming the persons who have committed such corrupt

practices, date, place and time the commission of such corrupt practices and as such lacks in material facts and material particulars about the corrupt practices, as required under Section 83 of the Act of 1951.The verification and affidavit attached with the petition are not in accordance with the provisions of Section 83 (1) (c) of the Act of 1951. The affidavit in support of corrupt practices is also not in accordance with law and as such the petition is not supported by affidavit and as such the verification of the pleadings is not in accordance with Order 6 Rules 14 and 15 of the Code of Civil Procedure as the petitioner has also not disclosed the source of information and in the absence of such declaration, the verification cannot be treated as valid verification.

5. The petitioner, in reply to the application filed by the respondent No. 1, denied that the election petition does not disclose any cause of action and the application at this stage under Order 7 Rule 11 is not maintainable on the grounds taken by the respondent No. 1. It has been submitted by the petitioner that all the necessary material facts and material particulars have been averred by the petitioner in paragraph 10 of the petition and the grounds taken by the respondent No. 1 is baseless. It is submitted by the petitioner that the pleading on the petition is almost supported by documentary evidence as the facts pleaded in the election petition are specific and the same concise material facts and even material particulars and the objection raised by the respondent No. 1 relates to evidence and the same shall be proved by the petitioner by oral evidence.

6. In reply to the objection of the respondent No. 7, the petitioner has submitted that the petitioner has complied with the requirement under Section 81 (3) of the Act of 1951 as the respondent No. 7 has accepted the true copies of the election petition. Whether compliance of Section 81, 82 and 117 has been made by the petitioner at the time of filing of the petition is to be ascertained by the ministerial staff of the Court and the petition has been found to be in order and therefore, there is no further scope of enquiry for the purpose of Section 86. However, the non-compliance of requirement of Section 83 of the Act is a judicial function and the same has not been specified as a ground for dismissal of the election petition under Section 86 of the Act of 1951. In view of the fact that the Registry of the High Court has certified that there was no defect in the petition, a presumption is attached that the petition was in order. The objection that allegation of corrupt practices is not supported by the affidavit of the petitioner has been denied and it is submitted that the source of information has been well pleaded and the affidavit to that effect has been filed along with the election petition. The verification is strictly in accordance with law and mandatory provision of proper verification has been complied with.

7. The objections of the respondents No. 1 and 7 may be categorized as such :-

A. That, the petition is bereft of material facts and material particulars relating to the alleged corrupt practices ;

B. That, the verification and affidavit to be filed by the election petitioner with the petition based on ground of corrupt practices do not conform to Rule 94 (A) in Form 25 ;

C. The copies of the petition supplied to the respondents are not the true copies of the petition and there is a violation of Section 81 (3) of the Act of 1951.

8. Shri B. P. Sharma, learned counsel for the respondent No. 1 citing various judgments of the Hon'ble Supreme Court submits that to unseat a returned candidate on the ground of corrupt practices, the same must be specifically alleged and strictly proved to have been committed by the returned candidate himself or by his election agent or by a person concerned with consent of the returned candidate or of his election agent. The pleading plays important role in an election petition and the same should be strictly in accordance with Section 83 of the Act of 1951 which provides that the petition contains a concise statement of the material facts on which the petitioner relies and should also set forth full particulars of the corrupt practice that he alleges with full details of the persons involved in such corrupt practices along with the date and place of the commission of each of such corrupt practice. It is further requirement of law that the charge of corrupt practice should be supported by an affidavit and the petitioner is also obliged to disclose the source of information in respect of the information of the corrupt practice, so that the petitioner can be bound for the charges leveled by him.

9. Dealing each and every instance of the alleged corrupt practice mentioned in the paragraph 10 of the petition, learned counsel for the respondent No. 1 submits that all the allegations of the corrupt practices are bereft of material facts and the same may be struck off from the pleadings and thus the petitioner has no cause of action to file the instant petition and the petition deserves to be dismissed in *limine*. He further submits that the copies of the election petition supplied to the respondents are not the true copies of the election petition as the affidavit in accordance with Rule 94 in Form 25 does not bear the notarial endorsement. He further submits that in paragraph 10 (h) of the petition, handwritten interpolation has been made by the petitioner however, in the copies supplied to the respondents, handwritten interpolation in para 10 (h) is missing, and therefore, the respondent No. 1 has not taken this pleading (interpolation) as a ground in his application for summary dismissal of the election petition.

10. Advancing similar arguments, Shri B. P. Gupta, learned counsel appearing for respondent No. 7 submits that the respondents have not been supplied with the true copies of the election petition filed by the election petitioner in the Court as the copy supplied to the respondent No. 1 does not contain the affidavit in Form No. 25 bearing notarial endorsement. He further submits that even the check report given by the ministerial authority of the High Court which is available on record, Sr. No. 6 demonstrates that the petition is accompanied by necessary copies of the petition and process fee but it does not show that the election petition was accompanied by the necessary true copies of the petition. He further points out that the affidavit filed by the petitioner in Form 25 does not conform to the requirment of Section 83 (1) (c) as from a bare perusal of the affidavit sworn by the petitioner as per the requirement of Section 83 (1) (c) of the Act of 1951, would go to show that in para (a) of the affidavit, the deponent has sworn that paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of distributing wine and money and particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the same are true to my knowledge ; wherein in paragraph 'd' of the affidavit, the deponent has further stated that the contents of para 10 (a, b, c, d, e, h, i, j) and 11, 12 are true to my information. He further submits that the true copies supplied to the respondents do not bear the endorsement of the true copy. The affidavit in Form 25 does not bear the notarial endorsement and the handwritten part of para 10 (h) of the petition is missing in *toto* from the copies supplied to the respondents and as such there is a complete non-compliance of Section 81 (3) of the Act of 1951.

11. On the other hand, Mrs. Hameeda Siddiqui learned counsel for the petitioner protesting the above objections contended that the compliance of Sections 81, 82 and 117 is to be seen at the time of presentation of the petition as the same is a ministerial act. Once the petition is accepted after verification by the ministerial staff of the High Court, no scope remains for further enquiry for the purposes of section 86 of the Act of 1951 to ascertain the deficiency in the election petition. She further submits that whether the petition is in accordance with Section 83 of the Act is a judicial function of the election tribunal and any deficiency in this regard does not render the petition to be dismissed in *limine* and the petition cannot be dismissed under Section 86 (1) of the Act as the High Court can dismiss an election petition under this provision where the petitioner does not comply with the provisions of Section 81, 82 and 117 of the Act. She further submits that the material facts and material particulars have been given in detail in para 10 of the petition. The allegations are supported by documents and, therefore, the contention of the respondents that the petition does not disclose the cause of action for want of material facts and particulars with respect to the corrupt practices is without substance. The above application is filed by the respondents with a view to delay the proceedings, the affidavit is in conformity with Rule 94 (A) of the Act of 1951 and the same is in Form 25. It is in accordance with Section 83 (1) (c) of the Act, therefore, the applications preferred by the respondents deserve to be dismissed being devoid of substance and the same have been filed with and ulterior motive to delay the proceedings.

12. I have heard the learned counsel for the parties. I have perused the petition and its annexures.

13. The first objection of the respondents is that the petition is bereft of material facts and material particulars of the alleged corrupt practices adopted by the respondent No. 1 and the pleading is not in accordance with Section 83 of the Act of 1951.

14. The specific instances of the corrupt practices adopted by the respondent No. 1 have been detailed in para 10 of the petition.

15. In para 10 (a), the allegation is that the respondent No. 2 received information from party workers of Bhartiya Janta Party of village Bordi and Ganda Bordi on 22-11-2003 to the effect that posters and banners were torn and destroyed by the police officials whereupon he lodged a report of Annexure P-2 with the Chief Election Officer. The document of Annexure P-2 or averments in the petition are against the police personnel and the same does not even remotely refer the respondent No. 1 and there is no allegation against the respondent No. 1.

16. In para 10 (b) of the petition, it is alleged that the respondent No. 1 was the Home Minister. It is further alleged that several criminal persons naming few of them against whom warrants were issued from different Courts have constituted an assembly of criminal elements and they were being used by the respondent No. 1 for canvassing and for threatening the other candidates of the election 2003. Further allegation is that when the respondent No. 2 was in a public meeting on 24-11-2003, he saw these criminals attacking his party workers upon which he lodged a report with the State Election Officer vide Ex. P-3. The document of Ex. P-3 being a complaint by respondent No. 2 contains allegations against couple of individuals that they have formed gang of 70-80 persons from various other parts of the State against whom warrants of arrest have been issued by the Courts and they armed with weapons are canvassing in favour of the respondent No. 1 by terrorizing the voters. They were also seen with canvassing party of the Congress candidate. Allegation against the respondent No. 1 is that he was patronizing the unsocial elements and permitting them to canvass

in his constituency. Except in this paragraph and the document of Ex. P-3, except making general allegations against a couple of individuals that they are terrorizing the electorates and these unsocial elements are attacking the Bharatiya Janta Party workers and they have the patronage of respondent No. 1, no material fact has been given in this paragraph with respect to the persons/ workers who were allegedly terrorized by the above persons.

17. In para 10 (c) of the petition, the allegation is that the Tehsil office and Block office are distributing the amount of compensation from Rs. 300 to 3,000 to the villagers of villages due to heavy rains. Receiving this information, the party workers lodge Ex. P-4 to the Chief Election Officer. Ex.-P-4 mentions that amount of compensation is being disbursed by the employees of Block Office Kharsia and the same is being disbursed by giving an impression that the amount has been sent by respondent No. 1 and thus the electorates are being influenced in favour of the respondent No. 1 for furtherance of the prospect of the respondent No. 1. There is no allegation that the above act is being done with the consent of respondent No. 1 or his election agent or any other persons concerned with them and there is no material fact which constitutes corrupt practice as contemplated under Section 123 (7) of the Act.

18. In the paragraphs 10 (d, e and f), the petitioner has made an allegation that the respondent No. 1 distributed the pamphlets of Annexure P-5 and made an appeal for voting in the name of caste. The language of the pamphlets and the object behind publishing and distributing the libelous pamphlets amongst the electorates was to tarnish the image of respondent No. 6 in the eyes of voters who himself was a candidate in the election and who belongs to kalar community. It is further averred that the respondent No. 6 has made complaint of Annexure P-6. English translation of pamphlets Annexure P-5 is that - " Kalar society of the Assembly Constituency Kharsia Assembly appeals all the caste persons that some mischievous persons in the name of society, are spreading this information that our society has set up independent candidate and support him, though Kalar society has decided to elect the respondent No. 1 by a thumping majoring for overall development of Kharsia. The candidate using the name of the society is fraud and mischievous and all of you caste brothers very well recognize him."

"Respondent No. 1 who is committed to make all the villages of Kharsia Constituent Assembly as ideal villages, vote him in his election symbol, get him elected by historical votes." In the foot of this appeal name of numerous persons have been mentioned. This appeal also bears the photograph of respondent No. 1 and his election symbol. The Assistant Returning Officer, Kharsia has submitted a report to the District Returning Officer, Raigarh on 11-12-2003 wherein it is mentioned that the respondent No. 6 has filed a complaint to this effect to observers of Election Commission that some mischievous persons of his community under the banners of respondent No. 1 have distributed pamphlets in which without naming the independent candidate, he has been depicted as fraud and mischievous and the same has been distributed with a view to tarnish the image of respondent No. 6. The Assistant Returning officer has further stated that the above act is in violation of Ideal Code of Conduct as asking for voting in the name of caste or religion is prohibited and the pamphlets points towards the respondent No. 6 and the same may be taken as violation of Clause 3 of the Ideal Code of Conduct.

19. At this juncture, it would be appropriate to mention that an election petition filed at the behest of respondent No. 6 Shant Kumar Jaiswal on the same ground has been dismissed vide judgment dated 29-4-2005 and the same has been reported in AIR 2005 C. G. 18. Learned counsel for the respondent No. 1 submits that from a bare perusal of the above cited judgment, it is evident that in paragraph 8 of the petition, allegation is made that the petitioner under the corrupt practice printed number of pamphlets and distributed the same. The pamphlets in question was libelous as the image of the petitioner of that case was tarnished in the eyes of voters as the allegations were *per se* defamatory besides being false to the knowledge of respondent No. 1. In para 11 of that petition, an allegation was made that on 1-12-2002, the agents of respondents No. 1 namely Sukhdeo S/o. Tarachand Dansena engaged vehicles TATA SUMO CG 04-A-4899 and CG 04 ZP 1056 for bringing the voters for voting in favour of the respondent No. 1. The mater was reported to the police and thereafter complaint was filed before the Chief Election Officer against the above corrupt practice. However no action was taken place. This Court dealing with the allegations in that petition in its judgment, has not accepted the pleadings of that petition on the ground that material facts of the alleged corrupt practice and the source of information of the petitioner has not been pleaded as per the mandatory provisions of section 83 of the Act and accordingly the petition was dismissed at the threshold by allowing the application of the returned candidate-respondent No. 1 for dismissal of the petition under Order 7 Rule 11 of the C. P. C.

20. In the instant petition, in paragraph 10 (g), the petitioner has made allegation that the respondent No. 1 was distributing wine in village Dhanagar on 28-11-2003 and which was distributed amongst the voters on 1-12-2003 and the respondent No. 1 has also taken assurance of casting vote in favour of Panja Symol in the night of 28-11-2003. The respondent No. 1 was giving to villagers for giving votes to him.

21. In paragraph 10 (h) of the petition, it is alleged that on 30-11-2003 respondent No. 2 has given liquor and Rs. 5000/- to one Mr. Digambar @ Chhotu to be distributed amongst the voters of village Khokhra. The respondent No. 1 has also given an iron pot for common use of villagers of the same village. Since the respondent No. 1 was Home

Minister of the State, no general person was even daring to lodge any complaint against him. with respect to this paragraph, the respondent has brought to the notice of this Court that true copies supplied to the respondents do not contain the handwritten part which finds place in line 4 after the word- the respondent No. 1 has also "*given an iron pot for*" common use of villagers of the same village. Learned counsel for the petitioner while arguing this ground did not mention above insertion as the same was not available with her at that time.

22. In para 10 (i), it is alleged that on 1-12-2003 early in the morning Nootam Patel, who is Asstt. Co-ordinator of B. J. P. Kamal Vahini was taken to police station Pusour and was kept there, so that he could not work for B. J. P. candidate. He was accompained by an active party worker of B. J. P. namely Suresh Kumar Sahu, who was also detained in the police station and this incident was reported vide Annexure P-7. However, on perusal of Annexure P-7, it is found that the contents of Annexure P-7 do not correspond to the allegations made in this paragraph and the same is not directed against the respondent No. 1.

23. In paragraph 10 (j) of the petition, it is alleged that the respondent No. 1 has used jeep No. C. G. 15 ZE-1228 on polling dated 1-12-2003 for transporting the voters of the constituency and report to the effect was lodged on 1-12-2003 by one Mr. Vinod Kumar as per Annexure P-8. From a perusal of Annexure P-8, it would be evident that a complaint has been lodged with the Presiding Officer, Kharsia alleging that jeep in question is being used for the purposes of transporting voters of Booth No. 52 and 53 in violation of Ideal Code of Conduct. No allegation is made against any person. Subsequently, it has been pleaded that the respondent No. 1 has incurred expenditure in contravention of Section 77 of the Act along with other contravention, which amounts to corrupt practices as contained in Section123 Sub-section 7 of the Act. Report was lodge by one Shrichand Ravlani vide Annexure P-9 and Annexure P-10. From a perusal of this written report of Annexure P-9 and P-10, it is found that various allegations of violation of Election Code of Conduct have been made like the Congress candidate used the Government building for campaigning, vehicles bearing loudspeakers are being plied without permission, officers posted at Kharsia have been named who are posted at Kharsia for more than 4 years who are engaged in election campaigning of the Home Minister directly and indirectly and their prayer to transfer them was not headed on the ground that they have not been deployed in the election duty.

24. First, we consider whether the pleading contain in paragraph 10 of the petition constitutes suffcient pleadings of the material facts as contained in Section 83 (1) of the Act of 1951 and thus gives cause of action to the petitioner to file the instant petition and whether even if the material fact in accordance with Section 83 (1) of the Act is not given, the petition could be dismissed in *limine* without trial.

25. Learned counsel for the petitioner relying upon the decision in Manohar Joshi-v-Nitin Bhaurao Patil reported in AIR 1996 SC 796 submits that the ground taken by the respondents that the petition is bereft of material facts constituting the corrupt practices as per Section 83 of the Act, though the necessary facts and particulars of the corrupt practices have been given by the petitioner nevertheless the ground that the petitioner has not pleaded material facts as per Section 83 (1) cannot be a ground to dismiss the petition under Section 86 of the Act since Section 86 makes deficiency in compliance of Section 81, 82 and 117 as a ground of dismissal of the petition and Section 83 is not specified as a ground for dismissal under Section 86.

26. In para 46 of the above judgment, it has been held as under :-

> "*46 The High Court failed to appreciate that the only allegation of corrupt practice in this election petition which raised a triable issue is as indicated above and rest of the general averments deficient in requisite pleadings of all the constituent parts of the corrupt practice did not constitute a pleading of the full cause of action and, therefore, had to be ignored and struck out in accordance with Order 6, Rule 16, C. P. C. However, there being a specific allegation in para 30 of the election petition relating to the returned candidate himself based on his speech made on 24-2-1990, to that extent a triable issued had been raised and had to be decided.*"

27. In Hardwari Lal-v- Kanwal Singh reported in AIR 1972 SC 515, it has been held that the election petition if does not set out material facts and particulars of the corrupt practices so as to furnish a cause of action, can be dismissed by virtue of Section 87 though not under Section 86 of the Act.

28. In the matters of Samant N. Balakrishnan-v-George Fernandez (AIR 1969 SC 1201 V 56) it has been held that first, Section 83 of the Act is mandatory and requires first a concise statement of material facts and then requires the fullest possible particulars. Second, omission of a single material fact leads to an incomplete cause of action and the statement of claim becomes bad. Third, the function of particulars is to present in full a picture of the cause of action to

make the opposite party understand the case he will have to meet. Fourth, material facts and particulars are distinct matters. Material facts will mention statements of fact and particulars will set out the names of persons with the date, time and place. Fifth, material facts will show the ground of corrupt practice and the complete cause of action and the particulars will give the necessary information to present a full picture of the cause of action. Sixth, in stating the material facts it will not do merely to quote the words of the section because then the efficacy of the material facts will be lost. The fact which consitutes a corrupt practice must be stated and the fact must be correlated to one of the heads of corrupt practice. Seventh, an election petition without the material facts relating to a corrupt practice is no election petition at all. A petition which merely cites the sections cannot be said to disclose a cause of action where the allegation is the obtaining or procuring of assistance unless the exact type and form of assistance and the person from whom it is sought and the manner in which the assistance is to further the prospects of the election are alleged as statements of facts.

29. Relying upon the above judgment, the Hon'ble Supreme Court in the matter of Azhar Hussain-v-Rajiv Gandhi reported in AIR 1986 SC 1253 has held that the petition can be dismissed for failure to incorporate in the petition the material facts and particulars relating to alleged corrupt practices and this power can be exercised at the threshold under Order 7 Rule 11 of C. P. C. Referring to Order 6 Rule 16 it has been held that the Court may at any stage of the proceedings, order to struck out or amend any pleading on the grounds mentioned in this rule.

30. In para 14, while dealing with the material facts it has been held that the material facts are the facts which if established would give the petitioner the relief asked for. The test required to be answered is whether the Court could have given a direct verdict in favour of the election petitioner in case the returned candidate had not appeared to oppose the election petition on the basis of the facts pleaded in the petition.

31. Similar is the view expressed in L. R. Shivaramagowda and others-v-T. M. Chandrashekar and others reported in (1999) 1 S C C 666 wherin it has been held that failure to plead material fact is fatal to the election petition and no amendment of the pleading can be allowed to introduce such material facts after the time-limit prescribed for filing the election petition, however, the absence of material particulars can be cured at a later stage by an appropriate amendment.

32. The Hon'ble Supreme Court in the matter of V. Narayanaswami-v- C.P. Thirunavukkarasu reported in (2000) 2 SCC 294, while elaborating the distinction between the material facts and material particulars has held that the petition has to be rejected at the outset in the absence of material facts but in case of defect in material particulars, it can be cured subsequently. It has been further held that where in spite of having sufficent opportunity to cure the defect in material particulars, petitioner fails to cure the defect, petition has to be rejected. It is not the duty of the High Court to *suo motu* direct the petitioner to furnish better particulars and the petition was dismissed at the threshold on the ground of lacking in material facts and material particulars, verification and affidavit.

33. In the matter of Jaipal Singh-v-Sumitra Mahajan (Smt.) and another reported in (2004) 4 SCC 522, referring Order 6 Rule 2 (1) of the C. P. C., it is declared that the pleading has to state material facts and not evidence. It explained the distinction between the material facts and material particulars. The material fact are the facts which are necessary to formulate a complete cause of action. Omission of a single material facts leads to an incomplete cause of action and subsequently the plaint becomes bad. In this judgment, to elaborate the distinction between the two, judgments, in the matters of Bruce-v-Odhams Press Ltd (1936) I All ER 287 (CA) has been referred, in which it has been observed that :

" The cardinal provision in Rule 4 is that the statement of claim must state the material facts. the word "material" means recessary for purpose of formulating a complete cause of action ; and if any one 'material' statement is omitted, the statement of claim is bad ; it is 'demurable' in the old phraseology and in the new is liable to be 'struck out' under RSC Order 25 Rule 4; or 'a further and better statement of claim' may be ordered under Rule 7.

The function of 'particulars' under Rule 6 is quite defferent. They are not to be used in order to fill material gaps in a demurrable statement of claim-gaps which ought to have been filled by appropriate statements of the various material facts which together constitute the Plaintiff's cause of action. The use of particulars is intended to meet a further and quite separate requirment of pleading, imposed in fairness and justice to the defendant. Their function is to fill the picture of the plaintiff's cause of action with information sufficiently detailed to put the defendant on his guard as to the case he had to meet and to enable him to prepare for trial."

34. The Hon'ble Supreme Court in the matters of Harmohinder Singh Pradhan-v-Ranjeet Singh Talwandi and others reported in (2005) 5 SCC 46 had an occasion to consider the corrupt practices under Section 123 (3) of the Act wherein it has been held that in order to constitute corrupt practice within the meaning of the above section, necessary ingredient is appeal on the ground of religion. Appeal to vote or refrain from voting on the ground of religion would be a material fact within the meaning of Clause (a) of sub-section (1) of Section 83 of the Act.

35. In the light of the principles and the law laid down in the aforesaid judgments, we propose to scrutinize the averments contained in paragraph 10 of the petition.

36. So far as the averments contained in para 10 (a, b and c) are concerned, there is not and iota of averments against respondent No. 1 to directly connect him with the offence alleged in the aforesaid paragraph. Para 10 (a) pertains torning out the posters and banners by police officials whereas para 10 (b) refers that certain named criminal persons against whom warrants were issued from different courts were being used by respondent No. 1 for the purpose of canvassing. Whereas para 10 (c) refers to disbursement of compensation by employees of Tehsil Office and Block office on the pretext that the same are being distributed from respondent No. 1. The pleadings in these paragraphs or documents of Annexure P-2, 3 and 4 at the most amount to electoral offences and the same cannot be termed corrupt practices as contemplated under Section 123 of the Act. Even otherwise the averments in petition and the contents of the documents are bereft of material fact which in no way connects the respondent No. 1 with the alleged offences. So far as the allegations in para 10 (d, e and f) are concerned, they refer to the distribution of pamphlets of Annexure P-5 by the respondent No. 1 which contains appeal for voting in the name of caste. Document of Annexure P-6 is a memo of Assistant Returning Officer, Kharsia addressed to District Returning Officer, Raigarh wherein it has been mentioned that Shant Kumar Jaiswal has lodged a report against some mischievous elements of the society under the banner of candidate of Congress in which without naming independent candidate he has been described as fraud and mischievous person and distribution of this pamphlets may tarnish his image and cause irreparable loss. From the pleading in these paragraphs, it is observed that there is no allegation against the respondent No. 1 that he was responsible for printing and publication of the pamphlets or that with his consent or with the consent of his election agent or any person concerned with them, the pamphlet was printed or published. The allegation is that the respondent No. 1 distributed the above pamphlets. The pamphlet of Annexure P-5 in paragraph 1 mentions that Kalar society has decided to elect the respondent No. 1 with thumping majority for overall development of the area an[illegible] in paragraph 2, there is an appeal for voting in favour of respondent No. 1 and the said appeal in this paragraph does not appeal in the name of caste. This appeal also does not refer the cast of respondent No. 1. In these paragraphs, the only allegation against the respondent No. 1 is that he was distributing the pamphlet however, no particulars regarding time, date, place or persons to whom the said pamphlet was distributed, have been given.

37. Similarly, in para 10 (g) of the petition, the petitioner claims that he saw the respondent No. 1 giving wine at village Dhanagar on 28-11-2003 which was distributed amongst the villagers on 1-12-2003. Who were the persons to whom the respondent No. 1 gave liquor for distribution has not been mentioned nor it has been mentioned that who in fact distributed the liquor amongst the villagers on 1-12-2003. In para 10 (h) also, the petitioner has incorporated a factum of corrupt practice by inserting that the respondent No.1 has given an iron pot for common use of villagers of the same village i. e. Khokhra. Here also name of the recipient of the iron pot has not been mentioned.

38. In the matters of R. P. Moidutty-v-P. T. Kunju Mohammad and another reported in (2000) 1 SCC 481, the Hon'ble Supreme Court while dealing the requirement of pleadings with respect to the material fact in election petition under Section 83 of the Act was seized with the matter wherein allegation of corrupt practices was to the effect that the elected candidate made an appeal on the ground of promotion of enmity or hatred on ground of religion, caste or community, and it was further alleged that the elected candidate prepared a script, directed and produced a video cassette (Vicharana) depicting demolition of Babri masque, the riots which broke out thereafter and extreme miseries of Muslims population affected by the riots and fixing responsibility for all the incidents on the then Prime Minister and President of the Congress Party which was supporting the election petitioner, it was held in para 18 of the judgment that the petition was bereft of material facts and material particulars as the same does not set out the names of even a few persons who viewed the film and/ or in whose presence it was exhibited, though it was not necessary for the petitioner to have alleged names of each and every person who have viewed the video film, however names of few persons who had viewed the film and in whose persons it was exhibited were expected to have been alleged in the petition so as to put the respondent on notice that these were the persons who were proposed to be examined by the petitioner in support of his averments. And, thus it was held that the petitioner's pleading in this regards fails to satisfy the requirement of Sub-section (1) of Section 83 of the Act as explained in Azhar Hussain's case (supra). In the instant case also the only allegation against the petitioner in paragraphs 10 (g) and (h) is that he distributed pamphlets, distributed liquor and gave iron pot to the unspecified persons. The name of not a single voter, who received the above article has been mentioned in the petition, therefore, this court is of the considered opinion that the petition is bereft of material particualrs and pleadings in this regard fail to satisfy requirement of Section 83 (1) of the Act.

39. So far as the allegations contained in para 10 (i) and 10 (j) are concerned, the allegations in this paragraphs are not directed against the respondent No. 1. more over, the document of Annexure P-7 and P-8 which are mentioned in this

paragraph and which are *reś-integra* of the petition do not correspond to the allegations contained in the paragraphs. The above documents do not make any allegation against respondent No. 1 and to that extent the averments in this paragraph wherein it is mentioned that Suresh Kumar Sahu made a report against the respondent No. 1 and respondent No. 1 used the jeep on polling on 1-12-2003 is factually incorret in the light of the above document.

40. Thus if the averments made in paragraph 10 are held to be bereft of material particulars of corrupt practices as described in Section 123 of the Act and accordingly the same are struck off as per Order 6 Rule 16 of the C. P. C., in that case, no material facts constituting corrupt practice under Section 123 of the Act remains in the petition. The respondent No. 1 and respondent No. 7 have filed these applications objecting that the petition does not contain the material facts constituting corrupt practices.

41. The petitioner has vehemently opposed the applications in its reply and stuck to the position that the petition does contain the material facts as prescribed under Section 83 (1) of the Act and she does not propose any amendment in the petition.

42. In the light of the above, the petition discloses no cause of action after the pleadings contained in para 10 are struck off and it deserves to be dismissed on the ground that it lacks material facts and particulars an accordingly it has to be dismissed under Order-7 Rule 11 C. C. P.

43. Apart from the above, the further objection taken is that the affidavit is not in accordance with Rule 94 (A) and the same is not in Form 25. There is no dispute that the instant petition has been filed solely on the ground of corrupt practices and, therefore according to Section 83 (1) (c), the petition was to be accompanied by an affidavit in Form 25 as per Rule 94 (A) of the Rules. If we go through the affidavit filed by the petitioner in compliance of the above provision, in paragraph (a) of the affidavit, which has been sworn before the Oath Commissioner shows that the statement contained in paragraph 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of distributing wine and money and particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the same petition are true to my knowledge. Whereas in para (d) it has been mentioned that the contents of para 10 (a, b, c, e, h, i, j) and 11 and 12 are true to my information. In para (c) the petitioner has stated that contents of para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (d, g) are true to my personal knowledge. Thus, the contents of affidavit in Form 25 filed by the petitioner are contradictory interse. We have already pointed out elsewhere that the pleadings with respect to documents Annexure 7 and 8 do not prima facie bear out from the contents of the document. However, the petitioner in his affidavit has also verified the above affidavit on oath.

44. The Supreme Court in the matter of L. R. Shivaramagowda (Supra), while dealing with the requirement of filing affidavit in the election petition based on corrupt practices while dealing Rule 94 (A) and Form 25, has held that the petition must disclose the source of information and clearly state which allegation is based on personal knowledge and which on information received, otherwise the affidavit cannot be held to be in conformity with Form 25 prescribed in Rule 94 (A) and the same is a very serious defect.

45. In the matter of V. Narayanaswamy (Supra), this aspect has been considered by the Supreme Court. In that case wherein learned counsel for the appellant argued that the petition should not have been thrown at the threshold and opportunity ought to have been given to the appellant to supply the material particulars, it has been held that the petitioner till date of impugned judgment persisted that the petition do not lack material particulars and verification was in accordance with the Code and affidavit in support of corrupt practices is in the Form 25 prescribed though admittedly that the petition lack material particulars, verification was not in accordance with the Code and affidavit did not conform to the Code prescribed. At the first opportunity, the respondent raised the objections that the petitions lacks with material facts and material particulars and that the verification of the petition and the affidavit were not in accordance with law however the petitioner persisted in his stand and termed the objections as irrelevant. Since the petitioner had an opportunity to supply the material particulars which were admittedly lacking and had also opportunity to amend the verification and to file affidavit in the form prescribed, but he failed to do so and accordingly it was held that the existence of material particualrs and affidavit are relevant and important when the petition is based on corrupt practices and in absence of those, the Court has jurisdiction to dismiss the petition.

46. The respondent No. 1 and 7 have submitted that the copies of petition supplied to them do not correspond to the original election petition and as such, the same is not true copy of the petition. It is contended that Section 81 (3) of the Act casts a duty upon the petitioner that the petition is to be accompanied by as many true copies thereof as there are respondents mentioned in the petition and the same are required to be attested by the petitioner under his own signatures that they are true copies. It is submitted that from the perusal of the endorsement of the A. R. (J) of the High Court in para 6, it is mentioned that "whether accompanied by necessary copies of petition and process fees-Yes". On the

basis of entries recorded on 21-1-2004, A. R. (J) has registered the petition without making any endorsement that the petition is accompanied by true copies of the petition or on verification the petition is found with no defect. Reliance is placed in the matter of Mithilesh Kumar Pandey-v-Baidyanath Yadav and others reported in AIR 1984 SC 305 where there were mistakes in the copy supplied to the elected candidate as regards names of the persons through whom the corrupt practices alleged to have been committed by him, it has been held that such mistakes are fatal and the petition was liable for dismissal in *limine.*

47. Further reliance is placed in the matter of Dr. (Smt.) Shipra-v-Shanti lal Khoiwal reported in AIR 1996 SC 1691 wherein it is mentioned that the petition was on the allegations of corrupt practices accompanied by affidavit as per Rule 94 (A) in Form 25. Copies of the petition supplied to the respondents and elected candidate did not contain endorsement of the notary in the affidavit filed in Form 25 as per Rule 94(A) of the Act. Dealing with the meaning of true copy in para 8 of the judgment, it was held that a true copy is a transcript identical or substitute to the original but not absolutely exact copy. But no body can by any possibility, misunderstand it to be not a true copy. It is seen that the test, as stated eariler, is whether by any variation from the original is to mislead an ordinary person. When the petitioner is enjoined to file an election petition accompanied by and affidavit duly sworn by the applicant duly verifying diverse allegations of corrupt practices imputed to the returned candidate and attested by the prescribed authority, it would be obvious that the statute intended that it shall be performed in the same manner as prescribed in Form 25 read with Rule 94-A of the Rules. With the above findings, the appeal preferred by the appellant petitioner against the judgment of the election judge dismissing the petition under Section 81 (3) of the Act was decided in the following terms :-

> "The contention that the election petition cannot be dismissed under Section 86 at the threshold on account of the omission on the part of the Registry of the High Court to point out the same as per its procedure cannot be countenanced. Lapse on the part of the Registry is not and insurance to deny to the returned candidate the plea that the attestation of the affidavit and its certification to be a true copy is an integral part of the pleadings in the election petition. Sections 81, 83 (1) (c) and 86 read with Rule 94-A of the Rules and Form 25 are to be read, conjointly, as an integral scheme. When so read, if the Court finds on an objection, being raised by the returned candidate, as to the maintainability of the election petition, the Court is required to go into the question and decide the preliminary objection. In case the Court does not uphold the same, the need to conduct trial would arise. If the Court upholds the Preliminary objections, the election petition would result in dismissal at the threshold, as the Court is left with no option except to dismiss the same."

48. The above matter again has been discussed in the matters of T. M. Jacob-v-C. Poulose reported in (1999) 4 SCC 274 and it has been held that in Dr. Shipra's (supra) case on the basis of absence of "notarial endorsement" of the verification as well as absence of an "affirmation" or "oath" by the election petitioner, the returned candidate got the impression, on a perusal of the "true copy" of the affidavit, that there was no duly sworn and verified affidavit filed in support of the allegations of corrupt practice by the election petitioner. It was precisely on account of this "fatal" defect that K. Ramaswamy, J. opined that " the principle of substantial compliance cannot be accepted in the fact situation".

49. In the instant case also, the notarial endorsement of the verification and true copy supplied to the elected candidate is missing. Not only that, the copy supplied to the respondents does also not contain the relevant insertion by handwriting note in para 10 (h) and, therefore, it cannot be said that the true copy was, in fact, supplied to the respondents. The petitioner had an opportunity to cure the above defect but the petitioner has not taken any step in this regard till date dispite having opportunity to do the same.

50. Counsel for the petitioner places her reliance in the matters of Jugal Kishore Patnaik-v-Ratnakar Mohanti reported in AIR 1976 SC 2130 and in the matters of Manohar Joshi (supra) and it is argued that the petition was presented by the petitioner along with as many true copies of the petition as per Section 81 (3) of the Act and after verifying the same, the petition was accepted and the same was registered and, therefore, now it is not open to the respondents to pray for dismissal of the petition under Section 81 (3) of the Act of 1951 on the ground that true copies having not been supplied to them as there is no further scope for any further enquiry for the purposes of Section 86 to ascertain the deficiency as the verification is a ministerial act. She further submits that where there is deficiency in particulars, dismissal of the petition at the threshold is not proper and petitioner could be directed to supply particulars and make good the deficiency. Reliance is placed in the matters of Sardar Harcharan Singh Brar-v-Such Darshan Singh and others reported in 2004 AIR SCW 6205.

51. As stated in foregoing paragraphs, from the records of the case and the endorsement of the A.R. (J) it has been observed that at the time of filing of the petition, the Additional Registrar (J) has made an endorsement that as many copies as there are respondents have been filed by the petitioner. It is not mentioned that true copies have been filed. Thus relying upon the judgment of the Supreme Court in Dr. Shipra's case (Supra), which has been duly considered by the

Constitution Bench and further considering that objection preferred by respondent No. 7 is identical to that in the matters of Dr. Shipra (supra), and also considering that the copies supplied to the respondent do not contain the allegations of corrupt practices against the respondent No. 1 mentioned in para 10 (h) by ink and as such under no stretch of imagination, the same can be termed as true copy, this Court is of the opinion that the petition deserves to be dismissed for non-compliance of the Section 81 (3) of the Act of 1951.

52. Thus in view of the aforesaid analysis, the applications preferred by respondent No. 1 and respondent No. 7 deserve to be allowed and the same are accordingly allowed and the petition is dismissed for non-compliance of Section 81 (3), 83 (1) (c) and Rule 94 (A) of the Rules.

Judge
5-10-2006

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 17th July, 2007—26 Asadha, 1929 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/CG-LA/07/2004.— In pursuance of Section 106 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the judgment/order of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur Bench dated 05-10-2006 in Election Petition No. 07/2004.

By order

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

Election Petition No. 07/2004

PETITIONER - Naresh Kumar Patel s/o Shri Goverdhan Prashad, Aged about 35 years, Occu.- Agriculture, Resi. of Dhanagar, Tah. & Distt. Raigarh (C. G.).

VERSUS

RESPONDENTS -

1. Shri Nand Kumar Patel s/o Late Mahendra Singh Patel, Aged about 49 years, Resi. of Post Nandeli, Tah. & Distt. Raigarh (C. G.), Assembly Constituency, Kharsia.

2. Laxmi Prasad Patel s/o Late Doulat Ram Patel, Aged about 62 years, Resi. of Village Chhuhipali, Post- Patel Pali, Distt. Raigarh (C. G.).

3. Vishnu Tiwari s/o Late Shatrudhan Tiwari, Aged about 55 years, Resi. of Village Telicote, Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

4. Bhaiyalal s/o not khown, Aged about 50 years, Gorepar, Tah.-Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

5. Ujagar Lal Verma s/o not known, P. O. Botalda, Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.)

6. Shant Kumar s/o Salikram, Aged About 52 years, Resi. of Tah.- Kharsia, Distt. Raigarh (C.G.).

7. Harilal Patel s/o not konwn, Aged about 53 years, Resi. of Village & Post Nagoi., Tah. Kharsia, Distt. Raigarh (C. G.).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

ELECTION PETITION No. 07/2004

Naresh Kumar Patel

Versus

Shri Nand Kumar Patel & others

Present : Smt. Hameeda Siddiqui, Adv. for the petitioner.

Shri B. P. Sharma, Adv. for the respondent No. 1.

Shri M. K.Bhaduri, Adv. for the respondent No. 4

Shri B. P. Gupta, Adv. for the respondent No. 7

ORDER

Per Dhirendra Mishra, J.

This order shall dispose of I. A. No. 2564/2006 filed by respondent No. 1, an application under order 7 Rule 11 of C.P.C. and I. A. No.2685/2006 filed by respondent No.7 under Order 7 Rule 11 of C. P. C. for dismissing the election petition in *limine* for non-compliance of the mandatory requirement of Representation of People's Act, 1951 and the rules made thereunder (hereinafter referred to as the Act of 1951 and Rules).

2. The petitioner being registered as Electoral in 18, Kharsia Assembly Constituency has filed this Election Petition under Section 80 and 80 A of the Act of 1951 for declaring the election of respondent No. 1 as a Member of Legislative Assembly from Constituency No. 18, Kharsia, district Raigarh as illegal and void on the ground that he resorted to the corrupt practices during the election as contemplated in Sub-section 1, 5 and 7 of Section 123 of the Act of 1951. The detail election programme is given in paragraph 2 of the petition and the respondent No.1 was declared elected by a margin of 32,768 votes from the respondent No. 2 on the election counting which was held on 4-12-2003.

3. The respondent No. 1 has filed the above application and has prayed for dismissal of the petition at the threshold on the ground that the material fact and material particulars relating to the alleged corrupt practices averred in para 10 (a) to 10 (j) of the petition do not disclose cause of action and the allegations and particulars are not pleaded and the petition is bereft of material facts/ material particulars. Apart from the above, the respondent No. 1 has aslo taken a ground that the verification contained in affidavit does not conform to the Form prescribed under the law.

4. Similarly, the sum and substance of the application preferred by the respondent No. 7 is that the election petition do not accompany with as many true copies as per Section 81 (3) of the Act of 1951 and copy of the petition supplied to the respondent was not the true copy of the petition as the copy supplied to the respondent does not bear the signature of the petitioner nor it does contain the verification. The verification and affidavit supplied to the respondent does not contain the signature of the petitioner and the copies supplied to the respondent which is accompanied by affidavit does not contain the seal and signature of the oath commissioner and thus there is a total non-compliance of the mandatory provisions of Section 81 (3) of the Act of 1951 and for this reason, it deserves to be dismissed. A further objection is that the petition does not include the statement naming the persons who have committed such corrupt

practices, date, place and time the commission of such corrupt practices and as such lacks in material facts and material particulars about the corrupt practices, as required under Section 83 of the Act of 1951.The verification and affidavit attached with the petition are not in accordance with the provisions of Section 83 (1) (c) of the Act of 1951. The affidavit in support of corrupt practices is also not in accordance with law and as such the petition is not supported by affidavit and as such the verification of the pleadings is not in accordance with Order 6 Rules 14 and 15 of the Code of Civil Procedure as the petitioner has also not disclosed the source of information and in the absence of such declaration, the verification cannot be treated as valid verification.

5. The petitioner, in reply to the application filed by the respondent No. 1, denied that the election petition does not disclose any cause of action and the application at this stage under Order 7 Rule 11 is not maintainable on the grounds taken by the respondent No. 1. It has been submitted by the petitioner that all the necessary material facts and material particulars have been averred by the petitioner in paragraph 10 of the petition and the grounds taken by the respondent No. 1 is baseless. It is submitted by the petitioner that the pleading on the petition is almost supported by documentary evidence as the facts pleaded in the election petition are specific and the same concise material facts and even material particulars and the objection raised by the respondent No. 1 relates to evidence and the same shall be proved by the petitioner by oral evidence.

6. In reply to the objection of the respondent No. 7, the petitioner has submitted that the petitioner has complied with the requirement under Section 81 (3) of the Act of 1951 as the respondent No. 7 has accepted the true copies of the election petition. Whether compliance of Section 81, 82 and 117 has been made by the petitioner at the time of filing of the petition is to be ascertained by the ministerial staff of the Court and the petition has been found to be in order and therefore, there is no further scope of enquiry for the purpose of Section 86. However, the non-compliance of requirement of Section 83 of the Act is a judicial function and the same has not been specified as a ground for dismissal of the election petition under Section 86 of the Act of 1951. In view of the fact that the Registry of the High Court has certified that there was no defect in the petition, a presumption is attached that the petition was in order. The objection that allegation of corrupt practices is not supported by the affidavit of the petitioner has been denied and it is submitted that the source of information has been well pleaded and the affidavit to that effect has been filed along with the election petition. The verification is strictly in accordance with law and mandatory provision of proper verification has been complied with.

7. The objections of the respondents No. 1 and 7 may be categorized as such :-

A. That, the petition is bereft of material facts and material particulars relating to the alleged corrupt practices ;

B. That, the verification and affidavit to be filed by the election petitioner with the petition based on ground of corrupt practices do not conform to Rule 94 (A) in Form 25 ;

C. The copies of the petition supplied to the respondents are not the true copies of the petition and there is a violation of Section 81 (3) of the Act of 1951.

8. Shri B. P. Sharma, learned counsel for the respondent No. 1 citing various judgments of the Hon'ble Supreme Court submits that to unseat a returned candidate on the ground of corrupt practices, the same must be specifically alleged and strictly proved to have been committed by the returned candidate himself or by his election agent or by a person concerned with consent of the returned candidate or of his election agent. The pleading plays important role in an election petition and the same should be strictly in accordance with Section 83 of the Act of 1951 which provides that the petition contains a concise statement of the material facts on which the petitioner relies and should also set forth full particulars of the corrupt practice that he alleges with full details of the persons involved in such corrupt practices along with the date and place of the commission of each of such corrupt practice. It is further requirement of law that the charge of corrupt practice should be supported by an affidavit and the petitioner is also obliged to disclose the source of information in respect of the information of the corrupt practice, so that the petitioner can be bound for the charges leveled by him.

9. Dealing each and every instance of the alleged corrupt practice mentioned in the paragraph 10 of the petition, learned counsel for the respondent No. 1 submits that all the allegations of the corrupt practices are bereft of material facts and the same may be struck off from the pleadings and thus the petitioner has no cause of action to file the instant petition and the petition deserves to be dismissed in *limine*. He further submits that the copies of the election petition supplied to the respondents are not the true copies of the election petition as the affidavit in accordance with Rule 94 in Form 25 does not bear the notarial endorsement. He further submits that in paragraph 10 (h) of the petition, handwritten interpolation has been made by the petitioner however, in the copies supplied to the respondents, handwritten interpolation in para 10 (h) is missing, and therefore, the respondent No. 1 has not taken this pleading (interpolation) as a ground in his application for summary dismissal of the election petition.

10. Advancing similar arguments, Shri B. P. Gupta, learned counsel appearing for respondent No. 7 submits that the respondents have not been supplied with the true copies of the election petition filed by the election petitioner in the Court as the copy supplied to the respondent No. 1 does not contain the affidavit in Form No. 25 bearing notarial endorsement. He further submits that even the check report given by the ministerial authority of the High Court which is available on record, Sr. No. 6 demonstrates that the petition is accompanied by necessary copies of the petition and process fee but it does not show that the election petition was accompanied by the necessary true copies of the petition. He further points out that the affidavit filed by the petitioner in Form 25 does not conform to the requirment of Section 83 (1) (c) as from a bare perusal of the affidavit sworn by the petitioner as per the requirement of Section 83 (1) (c) of the Act of 1951, would go to show that in para (a) of the affidavit, the deponent has sworn that paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of distributing wine and money and particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the same are true to my knowledge ; wherein in paragraph 'd' of the affidavit, the deponent has further stated that the contents of para 10 (a, b, c, d, e, h, i, j) and 11, 12 are true to my information. He further submits that the true copies supplied to the respondents do not bear the endorsement of the true copy. The affidavit in Form 25 does not bear the notarial endorsement and the handwritten part of para 10 (h) of the petition is missing in *toto* from the copies supplied to the respondents and as such there is a complete non-compliance of Section 81 (3) of the Act of 1951.

11. On the other hand, Mrs. Hameeda Siddiqui learned counsel for the petitioner protesting the above objections contended that the compliance of Sections 81, 82 and 117 is to be seen at the time of presentation of the petition as the same is a ministerial act. Once the petition is accepted after verification by the ministerial staff of the High Court, no scope remains for further enquiry for the purposes of section 86 of the Act of 1951 to ascertain the deficiency in the election petition. She further submits that whether the petition is in accordance with Section 83 of the Act is a judicial function of the election tribunal and any deficiency in this regard does not render the petition to be dismissed in *limine* and the petition cannot be dismissed under Section 86 (1) of the Act as the High Court can dismiss an election petition under this provision where the petitioner does not comply with the provisions of Section 81, 82 and 117 of the Act. She further submits that the material facts and material particulars have been given in detail in para 10 of the petition. The allegations, are supported by documents and, therefore, the contention of the respondents that the petition does not disclose the cause of action for want of material facts and particulars with respect to the corrupt practice is without substance. The above application is filed by the respondents with a view to delay the proceedings, the affidavit is in conformity with Rule 94 (A) of the Act of 1951 and the same is in Form 25. It is in accordance with Section 83 (1) (c) of the Act, therefore, the applications preferred by the respondents deserve to be dismissed being devoid of substance and the same have been filed with and ulterior motive to delay the proceedings.

12. I have heard the learned counsel for the parties. I have perused the petition and its annexures.

13. The first objection of the respondents is that the petition is bereft of material facts and material particulars of the alleged corrupt practices adopted by the respondent No. 1 and the pleading is not in accordance with Section 83 of the Act of 1951.

14. The specific instances of the corrupt practices adopted by the respondent No. 1 have been detailed in para 10 of the petition.

15. In para 10 (a), the allegation is that the respondent No. 2 received information from party workers of Bhartiya Janta Party of village Bordi and Ganda Bordi on 22-11-2003 to the effect that posters and banners were torn and destroyed by the police officials whereupon he lodged a report of Annexure P-2 with the Chief Election Officer. The document of Annexure P-2 or averments in the petition are against the police personnel and the same does not even remotely refer the respondent No. 1 and there is no allegation against the respondent No. 1.

16. In para 10 (b) of the petition, it is alleged that the respondent No. 1 was the Home Minister. It is further alleged that several criminal persons naming few of them against whom warrants were issued from different Courts have constituted an assembly of criminal elements and they were being used by the respondent No. 1 for canvassing and for threatening the other candidates of the election 2003. Further allegation is that when the respondent No. 2 was in a public meeting on 24-11-2003, he saw these criminals attacking his party workers upon which he lodged a report with the State Election Officer vide Ex. P-3. The document of Ex. P-3 being a complaint by respondent No. 2 contains allegations against couple of individuals that they have formed gang of 70-80 persons from various other parts of the State against whom warrants of arrest have been issued by the Courts and they armed with weapons are canvassing in favour of the respondent No. 1 by terrorizing the voters. They were also seen with canvassing party of the Congress candidate. Allegation against the respondent No. 1 is that he was patronizing the unsocial elements and permitting them to canvass

in his constituency. Except in this paragraph and the document of Ex. P-3, except making general allegations against a couple of individuals that they are terrorizing the electorates and these unsocial elements are attacking the Bharatiya Janta Party workers and they have the patronage of respondent No. 1, no material fact has been given in this paragraph with respect to the persons/ workers who were allegedly terrorized by the above persons.

17. In para 10 (c) of the petition, the allegation is that the Tehsil office and Block office are distributing the amount of compensation from Rs. 300 to 3,000 to the villagers of villages due to heavy rains. Receiving this information, the party workers lodge Ex. P-4 to the Chief Election Officer. Ex.-P-4 mentions that amount of compensation is being disbursed by the employees of Block Office Kharsia and the same is being disbursed by giving an impression that the amount has been sent by respondent No. 1 and thus the electorates are being influenced in favour of the respondent No. 1 for furtherance of the prospect of the respondent No. 1. There is no allegation that the above act is being done with the consent of respondent No. 1 or his election agent or any other persons concerned with them and there is no material fact which constitutes corrupt practice as contemplated under Section 123 (7) of the Act.

18. In the paragraphs 10 (d, e and f), the petitioner has made an allegation that the respondent No. 1 distributed the pamphlets of Annexure P-5 and made an appeal for voting in the name of caste. The language of the pamphlets and the object behind publishing and distributing the libelous pamphlets amongst the electorates was to tarnish the image of respondent No. 6 in the eyes of voters who himself was a candidate in the election and who belongs to kalar community. It is further averred that the respondent No. 6 has made complaint of Annexure P-6. English translation of pamphlets Annexure P-5 is that - " Kalar society of the Assembly Constituency Kharsia Assembly appeals all the caste persons that some mischievous persons in the name of society, are spreading this information that our society has set up independent candidate and support him, though Kalar society has decided to elect the respondent No. 1 by a thumping majoring for overall development of Kharsia. The candidate using the name of the society is fraud and mischievous and all of you caste brothers very well recognize him."

"Respondent No. 1 who is committed to make all the villages of Kharsia Constituent Assembly as ideal villages, vote him in his election symbol, get him elected by historical votes." In the foot of this appeal name of numerous persons have been mentioned. This appeal also bears the photograph of respondent No. 1 and his election symbol. The Assistant Returning Officer, Kharsia has submitted a report to the District Returning Officer, Raigarh on 11-12-2003 wherein it is mentioned that the respondent No. 6 has filed a complaint to this effect to observers of Election Commission that some mischievous persons of his community under the banners of respondent No. 1 have distributed pamphlets in which without naming the independent candidate, he has been depicted as fraud and mischievous and the same has been distributed with a view to tarnish the image of respondent No. 6. The Assistant Returning officer has further stated that the above act is in violation of Ideal Code of Conduct as asking for voting in the name of caste or religion is prohibited and the pamphlets points towards the respondent No. 6 and the same may be taken as violation of Clause 3 of the Ideal Code of Conduct.

19. At this juncture, it would be appropriate to mention that an election petition filed at the behest of respondent No. 6 Shant Kumar Jaiswal on the same ground has been dismissed vide judgment dated 29-4-2005 and the same has been reported in AIR 2005 C. G. 18. Learned counsel for the respondent No. 1 submits that from a bare perusal of the above cited judgment, it is evident that in paragraph 8 of the petition, allegation is made that the petitioner under the corrupt practice printed number of pamphlets and distributed the same. The pamphlets in question was libelous as the image of the petitioner of that case was tarnished in the eyes of voters as the allegations were *per se* defamatory besides being false to the knowledge of respondent No. 1. In para 11 of that petition, an allegation was made that on 1-12-2002, the agents of respondents No. 1 namely Sukhdeo S/o. Tarachand Dansena engaged vehicles TATA SUMO CG 04-A-4899 and CG 04 ZP 1056 for bringing the voters for voting in favour of the respondent No. 1. The mater was reported to the police and thereafter complaint was filed before the Chief Election Officer against the above corrupt practice. However no action was taken place. This Court dealing with the allegations in that petition in its judgment, has not accepted the pleadings of that petition on the ground that material facts of the alleged corrupt practice and the source of information of the petitioner has not been pleaded as per the mandatory provisions of section 83 of the Act and accordingly the petition was dismissed at the threshold by allowing the application of the returned candidate-respondent No. 1 for dismissal of the petition under Order 7 Rule 11 of the C. P. C.

20. In the instant petition, in paragraph 10 (g), the petitioner has made allegation that the respondent No. 1 was distributing wine in village Dhanagar on 28-11-2003 and which was distributed amongst the voters on 1-12-2003 and the respondent No. 1 has also taken assurance of casting vote in favour of Panja Symol in the night of 28-11-2003. The respondent No. 1 was giving to villagers for giving votes to him.

21. In paragraph 10 (h) of the petition, it is alleged that on 30-11-2003 respondent No. 2 has given liquor and Rs. 5000/- to one Mr. Digambar @ Chhotu to be distributed amongst the voters of village Khokhra. The respondent No. 1 has also given an iron pot for common use of villagers of the same village. Since the respondent No. 1 was Home

Minister of the State, no general person was even daring to lodge any complaint against him. with respect to this paragraph, the respondent has brought to the notice of this Court that true copies supplied to the respondents do not contain the handwritten part which finds place in line 4 after the word- the respondent No. 1 has also "*given an iron pot for*" common use of villagers of the same village. Learned counsel for the petitioner while arguing this ground did not mention above insertion as the same was not available with her at that time.

22. In para 10 (i), it is alleged that on 1-12-2003 early in the morning Nootam Patel, who is Asstt. Co-ordinator of B. J. P. Kamal Vahini was taken to police station Pusour and was kept there, so that he could not work for B. J. P. candidate. He was accompained by an active party worker of B. J. P. namely Suresh Kumar Sahu, who was also detained in the police station and this incident was reported vide Annexure P-7. However, on perusal of Annexure P-7, it is found that the contents of Annexure P-7 do not correspond to the allegations made in this paragraph and the same is not directed against the respondent No. 1.

23. In paragraph 10 (j) of the petition, it is alleged that the respondent No. 1 has used jeep No. C. G. 15 ZE-1228 on polling dated 1-12-2003 for transporting the voters of the constituency and report to the effect was lodged on 1-12-2003 by one Mr. Vinod Kumar as per Annexure P-8. From a perusal of Annexure P-8, it would be evident that a complaint has been lodged with the Presiding Officer, Kharsia alleging that jeep in question is being used for the purposes of transporting voters of Booth No. 52 and 53 in violation of Ideal Code of Conduct. No allegation is made against any person. Subsequently, it has been pleaded that the respondent No. 1 has incurred expenditure in contravention of Section 77 of the Act along with other contravention, which amounts to corrupt practices as contained in Section123 Sub-section 7 of the Act. Report was lodge by one Shrichand Ravlani vide Annexure P-9 and Annexure P-10. From a perusal of this written report of Annexure P-9 and P-10, it is found that various allegations of violation of Election Code of Conduct have been made like the Congress candidate used the Government building for campaigning, vehicles bearing loudspeakers are being plied without permission, officers posted at Kharsia have been named who are posted at Kharsia for more than 4 years who are engaged in election campaigning of the Home Minister directly and indirectly and their prayer to transfer them was not headed on the ground that they have not been deployed in the election duty.

24. First, we consider whether the pleading contain in paragraph 10 of the petition constitutes suffcient pleadings of the material facts as contained in Section 83 (1) of the Act of 1951 and thus gives cause of action to the petitioner to file the instant petition and whether even if the material fact in accordance with Section 83 (1) of the Act is not given, the petition could be dismissed in *limine* without trial.

25. Learned counsel for the petitioner relying upon the decision in Manohar Joshi-v-Nitin Bhaurao Patil reported in AIR 1996 SC 796 submits that the ground taken by the respondents that the petition is bereft of material facts constituting the corrupt practices as per Section 83 of the Act, though the necessary facts and particulars of the corrupt practices have been given by the petitioner nevertheless the ground that the petitioner has not pleaded material facts as per Section 83 (1) cannot be a ground to dismiss the petition under Section 86 of the Act since Section 86 makes deficiency in compliance of Section 81, 82 and 117 as a ground of dismissal of the petition and Section 83 is not specified as a ground for dismissal under Section 86.

26. In para 46 of the above judgment, it has been held as under :-

> *"46 The High Court failed to appreciate that the only allegation of corrupt practice in this election petition which raised a triable issue is as indicated above and rest of the general averments deficient in requisite pleadings of all the constituent parts of the corrupt practice did not constitute a pleading of the full cause of action and, therefore, had to be ignored and struck out in accordance with Order 6, Rule 16, C. P. C. However, there being a specific allegation in para 30 of the election petition relating to the returned candidate himself based on his speech made on 24-2-1990, to that extent a triable issued had been raised and had to be decided."*

27. In Hardwari Lal-v- Kanwal Singh reported in AIR 1972 SC 515, it has been held that the election petition if does not set out material facts and particulars of the corrupt practices so as to furnish a cause of action, can be dismissed by virtue of Section 87 though not under Section 86 of the Act.

28. In the matters of Samant N. Balakrishnan-v-George Fernandez (AIR 1969 SC 1201 V 56) it has been held that first, Section 83 of the Act is mandatory and requires first a concise statement of material facts and then requires the fullest possible particulars. Second, omission of a single material fact leads to an incomplete cause of action and the statement of claim becomes bad. Third, the function of particulars is to present in full a picture of the cause of action to

make the opposite party understand the case he will have to meet. Fourth, material facts and particulars are distinct matters. Material facts will mention statements of fact and particulars will set out the names of persons with the date, time and place. Fifth, material facts will show the ground of corrupt practice and the complete cause of action and the particulars will give the necessary information to present a full picture of the cause of action. Sixth. in stating the material facts it will not do merely to quote the words of the section because then the efficacy of the material facts will be lost. The fact which consitutes a corrupt practice must be stated and the fact must be correlated to one of the heads of corrupt practice. Seventh, an election petition without the material facts relating to a corrupt practice is no election petition at all. A petition which merely cites the sections cannot be said to disclose a cause of action where the allegation is the obtaining or procuring of assistance unless the exact type and form of assistance and the person from whom it is sought and the manner in which the assistance is to further the prospects of the election are alleged as statements of facts.

29. Relying upon the above judgment, the Hon'ble Supreme Court in the matter of Azhar Hussain-v-Rajiv Gandhi reported in AIR 1986 SC 1253 has held that the petition can be dismissed for failure to incorporate in the petition the material facts and particulars relating to alleged corrupt practices and this power can be exercised at the threshold under Order 7 Rule 11 of C. P. C. Referring to Order 6 Rule 16 it has been held that the Court may at any stage of the proceedings, order to struck out or amend any pleading on the grounds mentioned in this rule.

30. In para 14, while dealing with the material facts it has been held that the material facts are the facts which if established would give the petitioner the relief asked for. The test required to be answered is whether the Court could have given a direct verdict in favour of the election petitioner in case the returned candidate had not appeared to oppose the election petition on the basis of the facts pleaded in the petition.

31. Similar is the view expressed in L. R. Shivaramagowda and others-v-T. M. Chandrashekar and others reported in (1999) 1 S C C 666 wherin it has been held that failure to plead material fact is fatal to the election petition and no amendment of the pleading can be allowed to introduce such material facts after the time-limit prescribed for filing the election petition, however, the absence of material particulars can be cured at a later stage by an appropriate amendment.

32. The Hon'ble Supreme Court in the matter of V. Narayanaswami-v- C.P. Thirunavukkarasu reported in (2000) 2 SCC 294, while elaborating the distinction between the material facts and material particulars has held that the petition has to be rejected at the outset in the absence of material facts but in case of defect in material particulars, it can be cured subsequently. It has been further held that where in spite of having sufficent opportunity to cure the defect in material particulars, petitioner fails to cure the defect, petition has to be rejected. It is not the duty of the High Court to *suo motu* direct the petitioner to furnish better particulars and the petition was dismissed at the threshold on the ground of lacking in material facts and material particulars, verification and affidavit.

33. In the matter of Jaipal Singh-v-Sumitra Mahajan (Smt.) and another reported in (2004) 4 SCC 522, referring Order 6 Rule 2 (1) of the C. P. C., it is declared that the pleading has to state material facts and not evidence. It explained the distinction between the material facts and material particulars. The material fact are the facts which are necessary to formulate a complete cause of action. Omission of a single material facts leads to an incomplete cause of action and subsequently the plaint becomes bad. In this judgment, to elaborate the distinction between the two, judgments, in the matters of Bruce-v-Odhams Press Ltd (1936) I All ER 287 (CA) has been referred, in which it has been observed that :

" The cardinal provision in Rule 4 is that the statement of claim must state the material facts. the word "material" means recessary for purpose of formulating a complete cause of action ; and if any one 'material' statement is omitted, the statement of claim is bad ; it is 'demurable' in the old phraseology and in the new is liable to be 'struck out' under RSC Order 25 Rule 4; or 'a further and better statement of claim' may be ordered under Rule 7.

The function of 'particulars' under Rule 6 is quite defferent. They are not to be used in order to fill material gaps in a demurrable statement of claim-gaps which ought to have been filled by appropriate statements of the various material facts which together constitute the Plaintiff's cause of action. The use of particulars is intended to meet a further and quite separate requirment of pleading, imposed in fairness and justice to the defendant. Their function is to fill the picture of the plaintiff's cause of action with information sufficiently detailed to put the defendant on his guard as to the case he had to meet and to enable him to prepare for trial."

34. The Hon'ble Supreme Court in the matters of Harmohinder Singh Pradhan-v-Ranjeet Singh Talwandi and others reported in (2005) 5 SCC 46 had an occasion to consider the corrupt practices under Section 123 (3) of the Act wherein it has been held that in order to constitute corrupt practice within the meaning of the above section, necessary ingredient is appeal on the ground of religion. Appeal to vote or refrain from voting on the ground of religion would be a material fact within the meaning of Clause (a) of sub-section (1) of Section 83 of the Act

35. In the light of the principles and the law laid down in the aforesaid judgments, we propose to scrutinize the averments contained in paragraph 10 of the petition.

36. So far as the averments contained in para 10 (a, b and c) are concerned, there is not and iota of averments against respondent No. 1 to directly connect him with the offence alleged in the aforesaid paragraph. Para 10 (a) pertains torning out the posters and banners by police officials whereas para 10 (b) refers that certain named criminal persons against whom warrants were issued from different courts were being used by respondent No. 1 for the purposes of canvassing. Whereas para 10 (c) refers to disbursement of compensation by employees of Tehsil Office and Block office on the pretext that the same are being distributed from respondent No. 1. The pleadings in these paragraphs or documents of Annexure P-2, 3 and 4 at the most amount to electoral offences and the same cannot be termed corrupt practices as contemplated under Section 123 of the Act. Even otherwise the averments in petition and the contents of the documents are bereft of material fact which in no way connects the respondent No. 1 with the alleged offences. So far as the allegations in para 10 (d, e and f) are concerned, they refer to the distribution of pamphlets of Annexure P-5 by the respondent No. 1 which contains appeal for voting in the name of caste. Document of Annexure P-6 is a memo of Assistant Returning Officer, Kharsia addressed to District Returning Officer, Raigarh wherein it has been mentioned that Shant Kumar Jaiswal has lodged a report against some mischievous elements of the society under the banner of candidate of Congress in which without naming independent candidate he has been described as fraud and mischievous person and distribution of this pamphlets may tarnish his image and cause irreparable loss. From the pleading in these paragraphs, it is observed that there is no allegation against the respondent No. 1 that he was responsible for printing and publication of the pamphlets or that with his consent or with the consent of his election agent or any person concerned with them, the pamphlet was printed or published. The allegation is that the respondent No. 1 distributed the above pamphlets. The pamphlet of Annexure P-5 in paragraph 1 mentions that Kalar society has decided to elect the respondent No. 1 with thumping majority for overall development of the area and in paragraph 2, there is an appeal for voting in favour of respondent No. 1 and the said appeal in this paragraph does not appeal in the name of caste. This appeal also does not refer the cast of respondent No. 1. In these paragraphs, the only allegation against the respondent No. 1 is that he was distributing the pamphlet however, no particulars regarding time, date, place or persons to whom the said pamphlet was distributed, have been given.

37. Similarly, in para 10 (g) of the petition, the petitioner claims that he saw the respondent No. 1 giving wine at village Dhanagar on 28-11-2003 which was distributed amongst the villagers on 1-12-2003. Who were the persons to whom the respondent No. 1 gave liquor for distribution has not been mentioned nor it has been mentioned that who in fact distributed the liquor amongst the villagers on 1-12-2003. In para 10 (h) also, the petitioner has incorporated a factum of corrupt practice by inserting that the respondent No.1 has given an iron pot for common use of villagers of the same village i. e. Khokhra. Here also name of the recipient of the iron pot has not been mentioned.

38. In the matters of R. P. Moidutty-v-P. T. Kunju Mohammad and another reported in (2000) 1 SCC 481, the Hon'ble Supreme Court while dealing the requirement of pleadings with respect to the material fact in election petition under Section 83 of the Act was seized with the matter wherein allegation of corrupt practices was to the effect that the elected candidate made an appeal on the ground of promotion of enmity or hatred on ground of religion, caste or community, and it was further alleged that the elected candidate prepared a script, directed and produced a video cassette (Vicharana) depicting demolition of Babri masque, the riots which broke out thereafter and extreme miseries of Muslims population affected by the riots and fixing responsibility for all the incidents on the then Prime Minister and President of the Congress Party which was supporting the election petitioner, it was held in para 18 of the judgment that the petition was bereft of material facts and material particulars as the same does not set out the names of even a few persons who viewed the film and/ or in whose presence it was exhibited, though it was not necessary for the petitioner to have alleged names of each and every person who have viewed the video film, however names of few persons who had viewed the film and in whose persons it was exhibited were expected to have been alleged in the petition so as to put the respondent on notice that these were the persons who were proposed to be examined by the petitioner in support of his averments. And, thus it was held that the petitioner's pleading in this regards fails to satisfy the requirement of Sub-section (1) of Section 83 of the Act as explained in Azhar Hussain's case (supra). In the instant case also the only allegation against the petitioner in paragraphs 10 (g) and (h) is that he distributed pamphlets, distributed liquor and gave iron pot to the unspecified persons. The name of not a single voter, who received the above article has been mentioned in the petition, therefore, this court is of the considered opinion that the petition is bereft of material particualrs and pleadings in this regard fail to satisfy requirement of Section 83 (1) of the Act.

39. So far as the allegations contained in para 10 (i) and 10 (j) are concerned, the allegations in this paragraphs are not directed against the respondent No. 1. more over, the document of Annexure P-7 and P-8 which are mentioned in this

paragraph and which are *res-integra* of the petition do not correspond to the allegations contained in the paragraphs. The above documents do not make any allegation against respondent No. 1 and to that extent the averments in this paragraph wherein it is mentioned that Suresh Kumar Sahu made a report against the respondent No. 1 and respondent No. 1 used the jeep on polling on 1-12-2003 is factually incorret in the light of the above document.

40. Thus if the averments made in paragraph 10 are held to be bereft of material particulars of corrupt practices as described in Section 123 of the Act and accordingly the same are struck off as per Order 6 Rule 16 of the C. P. C., in that case, no material facts constituting corrupt practice under Section 123 of the Act remains in the petition. The respondent No. 1 and respondent No. 7 have filed these applications objecting that the petition does not contain the material facts constituting corrupt practices.

41. The petitioner has vehemently opposed the applications in its reply and stuck to the position that the petition does contain the material facts as prescribed under Section 83 (1) of the Act and she does not propose any amendment in the petition.

42. In the light of the above, the petition discloses no cause of action after the pleadings contained in para 10 are struck off and it deserves to be dismissed on the ground that it lacks material facts and particulars an accordingly it has to be dismissed under Order 7 Rule 11 C. C. P.

43. Apart from the above, the further objection taken is that the affidavit is not in accordance with Rule 94 (A) and the same is not in Form 25. There is no dispute that the instant petition has been filed solely on the ground of corrupt practices and, therefore according to Section 83 (1) (c), the petition was to be accompanied by an affidavit in Form 25 as per Rule 94 (A) of the Rules. If we go through the affidavit filed by the petitioner in compliance of the above provision, in paragraph (a) of the affidavit, which has been sworn before the Oath Commissioner shows that the statement contained in paragraph 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the accompanying election petition about the commission of the corrupt practice of distributing wine and money and particulars of such corrupt practice mentioned in paragraphs 10 (a, b, c, e, h, i, j) of the same petition are true to my knowledge. Whereas in para (d) it has been mentioned that the contents of para 10 (a, b, c, e, h, i, j) and 11 and 12 are true to my information. In para (c) the petitioner has stated that contents of para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (d, g) are true to my personal knowledge. Thus, the contents of affidavit in Form 25 filed by the petitioner are contradictory interse. We have already pointed out elsewhere that the pleadings with respect to documents Annexure 7 and 8 do not prima facie bear out from the contents of the document. However, the petitioner in his affidavit has also verified the above affidavit on oath.

44. The Supreme Court in the matter of L. R. Shivaramagowda (Supra), while dealing with the requirement of filing affidavit in the election petition based on corrupt practices while dealing Rule 94 (A) and Form 25, has held that the petition must disclose the source of information and clearly state which allegation is based on personal knowledge and which on information received, otherwise the affidavit cannot be held to be in conformity with Form 25 prescribed in Rule 94 (A) and the same is a very serious defect.

45. In the matter of V. Narayanaswamy (Supra), this aspect has been considered by the Supreme Court. In that case wherein learned counsel for the appellant argued that the petition should not have been thrown at the threshold and opportunity ought to have been given to the appellant to supply the material particulars, it has been held that the petitioner till date of impugned judgment persisted that the petition do not lack material particulars and verification was in accordance with the Code and affidavit in support of corrupt practices is in the Form 25 prescribed though admittedly that the petition lack material particulars, verification was not in accordance with the Code and affidavit did not conform to the Code prescribed. At the first opportunity, the respondent raised the objections that the petitions lacks with material facts and material particulars and that the verification of the petition and the affidavit were not in accordance with law however the petitioner persisted in his stand and termed the objections as irrelevant. Since the petitioner had an opportunity to supply the material particulars which were admittedly lacking and had also opportunity to amend the verification and to file affidavit in the form prescribed, but he failed to do so and accordingly it was held that the existence of material particuals and affidavit are relevant and important when the petition is based on corrupt practices and in absence of those, the Court has jurisdiction to dismiss the petition.

46. The respondent No. 1 and 7 have submitted that the copies of petition supplied to them do not correspond to the original election petition and as such, the same is not true copy of the petition. It is contended that Section 81 (3) of the Act casts a duty upon the petitioner that the petition is to be accompanied by as many true copies thereof as there are respondents mentioned in the petition and the same are required to be attested by the petitioner under his own signatures that they are true copies. It is submitted that from the perusal of the endorsement of the A. R. (J) of the High Court in para 6, it is mentioned that "whether accompanied by necessary copies of petition and process fees-Yes". On the

basis of entries recorded on 21-1-2004, A. R. (J) has registered the petition without making any endorsement that the petition is accompanied by true copies of the petition or on verification the petition is found with no defect. Reliance is placed in the matter of Mithilesh Kumar Pandey-v-Baidyanath Yadav and others reported in AIR 1984 SC 305 where there were mistakes in the copy supplied to the elected candidate as regards names of the persons through whom the corrupt practices alleged to have been committed by him, it has been held that such mistakes are fatal and the petition was liable for dismissal in *limine.*

47. Further reliance is placed in the matter of Dr. (Smt.) Shipra-v-Shanti lal Khoiwal reported in AIR 1996 SC 1691 wherein it is mentioned that the petition was on the allegations of corrupt practices accompanied by affidavit as per Rule 94 (A) in Form 25. Copies of the petition supplied to the respondents and elected candidate did not contain endorsement of the notary in the affidavit filed in Form 25 as per Rule 94(A) of the Act. Dealing with the meaning of true copy in para 8 of the judgment, it was held that a true copy is a transcript identical or substitute to the original but not absolutely exact copy. But no body can by any possibility, misunderstand it to be not a true copy. It is seen that the test, as stated eariler, is whether by any variation from the original is to mislead an ordinary person. When the petitioner is enjoined to file an election petition accompanied by and affidavit duly sworn by the applicant duly verifying diverse allegations of corrupt practices imputed to the returned candidate and attested by the prescribed authority, it would be obvious that the statute intended that it shall be performed in the same manner as prescribed in Form 25 read with Rule 94-A of the Rules. With the above findings, the appeal preferred by the appellant petitioner against the judgment of the election judge dismissing the petition under Section 81 (3) of the Act was decided in the following terms :-

> "The contention that the election petition cannot be dismissed under Section 86 at the threshold on account of the omission on the part of the Registry of the High Court to point out the same as per its procedure cannot be countenanced. Lapse on the part of the Registry is not and insurance to deny to the returned candidate the plea that the attestation of the affidavit and its certification to be a true copy is an integral part of the pleadings in the election petition. Sections 81, 83 (1) (c) and 86 read with Rule 94-A of the Rules and Form 25 are to be read, conjointly, as an integral scheme. When so read, if the Court finds on an objection, being raised by the returned candidate, as to the maintainability of the election petition, the Court is required to go into the question and decide the preliminary objection. In case the Court does not uphold the same, the need to conduct trial would arise. If the Court upholds the Preliminary objections, the election petition would result in dismissal at the threshold, as the Court is left with no option except to dismiss the same."

48. The above matter again has been discussed in the matters of T. M. Jacob-v-C. Poulose reported in (1999) 4 SCC 274 and it has been held that in Dr. Shipra's (supra) case on the basis of absence of "notarial endorsement" of the verification as well as absence of an "affirmation" or "oath" by the election petitioner, the returned candidate got the impression, on a perusal of the "true copy" of the affidavit, that there was no duly sworn and verified affidavit filed in support of the allegations of corrupt practice by the election petitioner. It was precisely on account of this "fatal" defect that K. Ramaswamy, J. opined that " the principle of substantial compliance cannot be accepted in the fact situation".

49. In the instant case also, the notarial endorsement of the verification and true copy supplied to the elected candidate is missing. Not only that, the copy supplied to the respondents does also not contain the relevant insertion by handwriting note in para 10 (h) and, therefore, it cannot be said that the true copy was, in fact, supplied to the respondents. The petitioner had an opportunity to cure the above defect but the petitioner has not taken any step in this regard till date dispite having opportunity to do the same.

50. Counsel for the petitioner places her reliance in the matters of Jugal Kishore Patnaik-v-Ratnakar Mohanti reported in AIR 1976 SC 2130 and in the matters of Manohar Joshi (supra) and it is argued that the petition was presented by the petitioner along with as many true copies of the petition as per Section 81 (3) of the Act and after verifying the same, the petition was accepted and the same was registered and, therefore, now it is not open to the respondents to pray for dismissal of the petition under Section 81 (3) of the Act of 1951 on the ground that true copies having not been supplied to them as there is no further scope for any further enquiry for the purposes of Section 86 to ascertain the deficiency as the verification is a ministerial act. She further submits that where there is deficiency in particulars, dismissal of the petition at the threshold is not proper and petitioner could be directed to supply particulars and make good the deficiency. Reliance is placed in the matters of Sardar Harcharan Singh Brar-v-Such Darshan Singh and others reported in 2004 AIR SCW 6205.

51. As stated in foregoing paragraphs, from the records of the case and the endorsement of the A.R. (J) it has been observed that at the time of filing of the petition, the Additional Registrar (J) has made an endorsement that as many copies as there are respondents have been filed by the petitioner. It is not mentioned that true copies have been filed. Thus relying upon the judgment of the Supreme Court in Dr. Shipra's case (Supra), which has been duly considered by the

Constitution Bench and further considering that objection preferred by respondent No. 7 is identical to that in the matters of Dr. Shipra (supra), and also considering that the copies supplied to the respondent do not contain the allegations of corrupt practices against the respondent No. 1 mentioned in para 10 (h) by ink and as such under no stretch of imagination, the same can be termed as true copy, this Court is of the opinion that the petition deserves to be dismissed for non-compliance of the Section 81 (3) of the Act of 1951.

52. Thus in view of the aforesaid analysis, the applications preferred by respondent No. 1 and respondent No. 7 deserve to be allowed and the same are accordingly allowed and the petition is dismissed for non-compliance of Section 81 (3), 83 (1) (c) and Rule 94 (A) of the Rules.

Judge
5-10-2006

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008—श्रावण 17, शक 1930

भाग 2

निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008—श्रावण 17, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी, उम्र 36 वर्ष, निवासी -बजरंग भवन, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर, थाना व तह. अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.) की हूं. विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी रंजना मार्डीकर आत्मजा श्री आनन्द राव मार्डीकर, निवासी-टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ. ग. था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपना नाम श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कु. रंजना मार्डीकर
आत्मजा-श्री आनन्द राव मार्डीकर
निवासी-टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती वर्षा जोशी
पति-श्री विकास कुमार जोशी
निवासी-बजरंग भवन, रिंग रोड
नमनाकला, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश शर्मा आत्मज श्री सालिक शर्मा, उम्र 43 साल, निवासी-ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद, थाना उतई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपनी पुत्री शालिनी , उम्र 13 वर्ष का नाम परिवर्तित कर कु. अपूर्वा शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. अपूर्वा शर्मा आत्मजा श्री हरीश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. शालिनी	कु. अपूर्वा शर्मा
आत्मजा-श्री हरीश शर्मा	आत्मजा-श्री हरीश शर्मा
निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद	निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद
तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश शर्मा आत्मज श्री सालिक शर्मा, उम्र 43 साल, निवासी-ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद, थाना उतई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपने पुत्र सतीश कुमार , उम्र 12 वर्ष का नाम परिवर्तित कर अशुतोष शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अशुतोष शर्मा आत्मजा श्री हरीश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सतीश कुमार	अशुतोष शर्मा
आत्मज-श्री हरीश शर्मा	आत्मज-श्री हरीश शर्मा
निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद	निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद
तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नेहा यादव पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा, उम्र 27 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नगर सुपेला, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं . मैं अपनी नाम परिवर्तित कर प्रतिमा थापा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे प्रतिमा थापा पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नेहा यादव	प्रतिमा थापा
पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा	पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा
निवासी लक्ष्मी नगर, सुपेला, भिलाई	निवासी लक्ष्मी नगर, सुपेला, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. अन्जू एन. मैथ्यू आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई, उम्र 24 साल, निवासी द्वारा श्री के. पी. चाको, प्रगति नगर रिसाली, 154/66, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उपनाम एन. मैथ्यू को परिवर्तित कर कु. अन्जू मथाई रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. अन्जू मथाई आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अन्जू एन. मैथ्यू आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई निवासी 154/66, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. अन्जू मथाई आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई निवासी 154/66, प्रगति नगर, रिसाली,भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

सराइपाली, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक क/वा-1/08.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सरायपाली के पंजीयन में रा. मा. क्र. ब-113 वर्ष 07-08 दर्ज दिनांक 10-10-07 पर ट्रस्ट का नाम माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट का पंजीयन दिनांक 17-7-2008 को किया गया है. इस ट्रस्ट की सम्पत्ति अनुसूची इस प्रकार है :-

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	श्री माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	साहित्य पुस्तकें 660 नग मूल्य 30792.00 रुपये अलमारी 2 नग मूल्य 5000.00 रुपये टेबल 2 नग मूल्य 2000.00 रुपये कुर्सिया 8 नग मूल्य 1600.00 रुपये बेंच 2 नग मूल्य 1400.00 रुपये नगद राशि 5000.00 रुपये

ट्रस्ट का परिवर्तित नाम-माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट, ट्रस्टियों की संख्या 1. अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र उपवेजा, कमल जनरल स्टोर्स पदमपुर रोड सरायपाली 2. उपाध्यक्ष-श्री त्रिलोचन पटेल ग्राम सरायपाली 3. सचिव-श्री शत्रुधन पुजारी, वार्ड क्रमांक 8 झिलमिला, 4. कोषाध्यक्ष-श्री बिहारीलाल अग्रवाल, सरसीवां मार्ग सरायपाली, 5. सह-सचिव-श्री संजय शर्मा, गीता भवन के पास सरायपाली, 6. सदस्य-श्री प्रमोद त्रिपाठी, ग्राम/पोस्ट बोंदा श्री रामचन्द्र अग्रवाल गणेश टी. बी. सेन्टर बसना.

अरविंद शर्मा,
रजिस्टार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक /परिसमापन/2008/1498.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हिर्री, विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3841 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओं सूचना जारी किया गया था. कारण बताओं सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने तथा भविष्य में, कार्यशील होने की संभावनाएं नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि रायपुर दुग्ध संघ से परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप समिति का कार्य बंद हो गया था. वर्तमान में रायपुर दुग्ध संघ द्वारा परिवहन व्यवस्था की जा चुकी है.

परिसमापक द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्समय परिवहन व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप समिति का कार्य बाधित हुआ था जो कि व्यवस्थित हो चुका है. वर्तमान में सभी सदस्य संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्ययन से समिति को पुर्नजीवन करना सदस्यों के हित में है.

अतः छ. ग. सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1522.—महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा, पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 24-11-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्र. 584 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1533.—किसान फलोद्यान एवं साग सब्जी उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया स. स., बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3502 दिनांक 24-4-93 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 863 दिनांक 24-4-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, किसान फलोद्यान एवं साग सब्जी उत्पादक वि. प्र. सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एल. एल. ध्रुव, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/20081555.—कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, तखतपुर, पंजीयन क्रमांक 181 दिनांक 13-12-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अनतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 1126 दिनांक 31-5-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, तखतपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1556.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/914/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2008 के तहत् सत्यम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, कस्तुरबा नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3586 दिनांक 20-1-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.